HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 16-30 जून, 2019

द रीव टाइम्स
The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 1/ अंक 23/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

मौसम का हाल

मौसम में हल्की बूंदाबांदी के साथ-साथ इस सप्ताह बारिश होने के कारण राहत मिलेगी। 16,18,19,21, 22,23,28 जून को बादल रहेंगे तथा बारिश की संभावना भी है। बाकि दिनों में मौसम शुष्क एवं गर्म बने रहने की उम्मीद है। हवाओं के कारण हल्का तुफान भी आने की संभावना बनी हुई है।

किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति का आगाज़ पहली सीढ़ी से ही होता है : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

द रीव टाइम्स में अन्दर पढ़ें.....

- पृष्ठ 2... विकास खण्ड मशोबरा में मिशन रीव की दस्तक
- पृष्ठ 3 से 6...ज़िलावार ख़बरें
- पृष्ठ 7...कानुन एवं स्वास्थ्य
- पृष्ठ 8...संपादकीय: Restructuring Indian Economy -A Perspective
- पृष्ठ 9...अभिव्यक्ति: जलने लगी है धरती...विनाश के स्पष्ट संकेत
- पृष्ठ 10...प्रादेशिक हिमाचल संपूर्ण
- पृष्ठ 11...राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 12...अंतर्राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 13...समसामयिक
- पृष्ठ 14...योजनाएं -प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
- पृष्ठ 15...प्रधानमंत्री आवास योजना
- पृष्ठ 16...रोचक समाचार

क्या कहते हैं पंचायत प्रतिनिधि

मिशन रीव की टीम ने पंचायत का दौरा किया है। यह एक अनूठा प्रयास लगा और रोजगार के क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए यह एक अनूठा प्रयास कहा जा सकता है। हालांकि हमें अभी इसे समझने की आवश्यकता है जिसके लिए अलग से युवाओं के साथ मिशन रीव की बैठक करवाई जाऐगी।

योगेश चौहान
उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मायली जेजड़

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा जब गांव की सेवा करते हुए ही एक स्थाई रोजगार की दिशा में कार्य करने के लिए कोई संस्था प्रयासरत है। मिशन रीव को समझने का प्रयास किया जा रहा है तथा आने वाले समय में लोगों के साथ इस मिशन पर चर्चा की जाएगी।

कृष्ण दत्त
प्रधान, ग्राम पंचायत भौंट

पंचायत प्रतिनिधियों को तो मिशन रीव की जानकारी प्राप्त हो रही है लेकिन इसकी आवश्यकता ग्रामीण युवाओं के लिए अधिक महत्व रखती है। इसके लिए मिशन रीव के साथ गांव के युवाओं एवं महिलाओं को भी बैठक में शामिल किया जाएगा तथा भविष्य में शीघ्र ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। हमारी पंचायत का पूर्ण सहयोग मिशन रीव को मिलेगा।

हीरानंद शर्मा
प्रधान, ग्राम पंचायत कोट

मिशन रीव को ग्राम पंचायत में पंचायत की ओर से हरसंभव सहयोग मिलेगा। हमारी ग्राम पंचायत के लोगों की सेवाओं में जो भी सेवाभाव से आगे आएगा उसको पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। इसे समझने के लिए भविष्य में लोगों के साथ एक बड़ी बैठक की जाएगी।

राम कृष्ण
प्रधान, ग्राम पंचायत पटगैहर

ज़िला शिमला में मिशन रीव संस्करण 2 ...

विकास खण्ड मशोबरा की 48 पंचायतों में मिशन रीव की धमक

लोगों से भी गांव में हुआ संपर्क / युवा मंडल, महिला मंडलों के साथ हुई चर्चा

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

मिशन रीव ने अपनी सेवाओं और घर - गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ज़िला शिमला में तुफानी आगाज़ से शुरुआत की है। इसके लिए सर्वप्रथम शिमला के विकास खण्ड मशोबरा को चयनित कर खण्ड की 48 पंचायतों में मिशन रीव के सेवाकर्मी वहां के पंचायत प्रतिनिधियों एवं सचिवों से मिले। इसके अलावा गांव में जाकर लोगों से भी रीव पर चर्चा की गई। विकास खण्ड में समस्त 48 पंचायतों में मिशन रीव के रीव ऐसोसियेटस की भर्ती की जानी है जिनकी संख्या ३ होगी। इन रीव एसोसियेटस के लिए एनएसडीसी प्रमाणित सर्टिफिकेट कोर्स होगा। आईआईआरडी एनएसडीसी के साथ अधिकारिक एसोसियेशन में है तथा हिमाचल में 10 हज़ार युवाओं को इस सर्टिफिकेट कोर्स का प्रषिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार की सुनिश्चितता भी बनाई गई है। यह रोजगार अपना गांव अथवा घर छोड़कर अन्य राज्यों या अन्यत्र नहीं बल्कि अपने ही गांव में प्रदान किया जा रहा है। यही इस मिशन रीव की मूल विशेषता भी है। इसके लिए रीव संस्करण 2 में सारी व्यवस्था एवं प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रारुप के अनुसार ही रखा गया है। रीव एसोसिएट्स आमजन की समस्त समस्याओं की सदस्यता के बाद आवश्यकता आकलन ऑनलाईन करने के बाद मिशन रीव की समस्त सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। उनके साथ एक ऐसा चैनल है तो गांव - पंचायत से शुरु होता है तथा विकास खण्ड, ज़िला एवं राज्य स्तर पर समस्याओं के निदान में सहयोग देगा। इन्हीं उद्देश्यों के लिए जनमानस को व्यापक पैमाने पर जोड़ने का लक्ष्य है तथा इसके लिए रीव टीम की 12 टीमें मशोबरा विकास खण्ड की 48 पंचायतों में पंचायत के प्रतिनिधियों एवं लोगों से मुखातिब हुए। इसके लिए रीव के पंपलैटस्, द रीव टाइम्स समाचार पत्र, पोस्टर एवं अन्य विवरण को विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया गया।

वैश्विक सराहना के बाद अब गांव-घर तक

विश्व भर में अपनी अनूठी पहल और महान सामाजिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के निर्वहन में अनूठी शैली के साथ अपनी पहचान बना चुका मिशन रीव हिमाचल में लगभग दो वर्षों से लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहा है। विकास खण्ड मशोबरा में समस्त पंचायतों में भी रीव की सेवाओं को सराहना मिली है। भ्रमण पर गई टीमों ने लोगों को इसकी समस्त विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की तथा रीव की सेवाओं के अलावा रोजगार के क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को अवसर प्रदान करने की वचनबद्धता पर प्रस्तुतिकरण किया। इसके अलावा एनएसडीसी से प्रमाणित सर्टिफिकेट कोर्स एवं पंचायतों में रीव सलाहकार बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पर भी विस्तृत चर्चा की गई। रीव सलाहकार बोर्ड में पंचायत के प्रतिनिधियों के अलावा गांव के समाजसेवियों, युवा एवं महिला मंडलों के प्रतिनिधियों, गांव के जागरुक बुजुर्ग आदि को प्रमुखता एवं प्राथमिकता के साथ स्थान दिया जा रहा है। यह बोर्ड मिशन रीव एवं गांव के जनमानस में एक पुल की तरह कार्य करेगा।

पंचायतों में मिशन रीव के लिए उत्सुकता

मशोबरा विकास खण्ड की 48 ग्राम पंचायतों में मिशन रीव के लिए लोगों में उत्साह दिखा। प्रधानों, उप-प्रधानों एवं सचिवों के अलावा वार्ड सदस्यों से भी मिशन रीव के सेवाकर्मी मिले। इस अवसर पर मिशन रीव क्या है और किस प्रकार यह आम लोगों की समस्याओं और जिम्मेवारी का संवाहक बन सकता है, इस पर लोगों से चर्चा की गई। ग्रामीणों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने इसकी समस्त गतिविधियों को ऑनलाईन करने पर पारदर्शिता की सराहना भी की है। विशुद्ध पारदर्शी तरीके से रीव एसोसिएट्स की भर्तियां एवं प्रशिक्षण होगा जिसमें ऑनलाईन प्रारुप को ही अपनाया जाऐगा। उसके बाद रीव सेवाओं के संवाहक के तौर पर सेवाकर्मी गांव-घर में जाकर लोगों की आवश्यकता आकलन को आधार बनाकर सेवाऐं प्रदान करेंगें। ग्रामीणों ने इस अवसर पर बहुत से जिज्ञासायें तथा प्रश्न सामने रखें जिसका निदान रीव टीम ने मौके पर ही किया तथा मिशन रीव की समस्त जानकारी ऑनलाईन www.missionriev.in पर कभी भी, कहीं भी ली जा सकती है।

आईआईआरडी के मुखपत्र द रीव टाइम्स की मांग बढ़ी

गांव - गांव में मिशन रीव एवं प्रदेश, देश व दुनिया की ख़बरों को लोगों की आवाज़ बनकर पहुंचाने में सफल रहे समाचार पत्र द रीव टाइम्स को भी लोगों ने खूब सराहा है। ग्रामीणों के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इस समाचार पत्र को पंचायत और गांव तक पहुंचाने की अपील की। गौरतलब है कि मिशन रीव की मूल सेवाओं का संवाहक एवं ख़बरों की पड़ताल में अग्रणी द रीव टाइम्स को पाठकों की खूब उत्साहवर्धक टिप्पणियां प्राप्त हो रही है।

रीव सचिवालय में होगी जन प्रतिनिधियों के साथ सहयोगात्मक चर्चा

इस ग्रामीण अभियान के बाद अब विकास खण्ड मशोबरा की समस्त पंचायतों के जन प्रतिनिधियों जिनमें आरंभिक रुप से प्रधान एवं उप प्रधान शामिल है, के साथ रीव सचिवालय शनान में चर्चा होगी तथा उनके सहयोग एवं प्रोत्साहन को सुनिश्चित बनाया जाएगा। इसमें मिशन रीव की सेवाओं एवं रीव सलाहकार बोर्ड के गठन पर भी चर्चा की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में आईआईआरडी का सराहनीय क़दम

कौशल विकास योजना में युवाओं को मिला रोजगार

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

उत्तर प्रदेश के चेहनिया चंदौली में डीडीयूजीकेवाई के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। दो बैच में चल रहे प्रशिक्षण में प्रथम बैच को प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद हरियाणा के फरुख़ा मिंडा में ये नौकरी प्रदान कर रोजगार दिया गया। गौरतलब है कि आईआईआरडी द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें से एक बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जा चुका है। उत्तर प्रदेशके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आईआईआरडी के इस प्रयास की सराहना कर चुके हैं तथा युवाओं को रोजगार के प्रमाणपत्र बांट चुके हैं । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बहुआयामी योजना के अंतर्गत प्रदेश में आईआईआरडी द्वारा युवाओं के लिए इस प्रकार के अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

विकास खण्ड मशोबरा की

ग्राम पंचायतों में मिशन रीव की दस्तक

हिमाचल में 25.16 फीसदी बढ़ गया बर्फीला इलाका

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बीते सीजन में भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल में बर्फीला इलाका 25.16 फीसदी बढ़ गया है। स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद के संयुक्त अध्ययन में यह बात सामने आई है।

सेंटर ने सेटेलाइट डेटा के आधार पर साल 2017–18 और 2018–19 में प्रदेश के चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज बेसिन के आसपास के बर्फीले इलाके का अक्तूबर से मार्च के बीच अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर सेंटर का दावा है कि 2018–19 में चारों बेसिन में भारी बर्फबारी हुई थी। प्रदेश की नदियों के पानी और मौसम की निगरानी के लिए हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट (हिमकॉस्ट) ने एचपी स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज और इसरो की मदद से चारों बेसिन का अध्ययन शुरू किया है। इसमें दोनों संस्थाओं ने 2017–18 और 2018 – 19 में बर्फीले क्षेत्रफल का तुलनात्मक अध्ययन किया है।

अध्ययन के अनुसार साल 2017–18 में जहां रावी, ब्यास, सतलुज और चिनाब बेसिन का बर्फीला क्षेत्र 97 हजार 672 वर्ग किलोमीटर था, वहीं 2018–19 में यह 25.16 फीसदी बढ़कर 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसमें 54.6 फीसदी की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी रावी बेसिन में दर्ज की गई है।

ब्यास बेसिन में 22.6 फीसदी, सतलुज में 20.8 और चिनाब में 23.2 फीसदी की वृद्धि हुई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बताया कि पिछले सीजन में सामान्य से दस फीसदी ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई थी। इसी बर्फबारी का नदियों के बेसिनों पर पड़े असर का अध्ययन किया है।

केन्द्र से करेगें बजट बढ़ाने की मांग : मुख्यमंत्री

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश सरकार द्वारा सीमान्त क्षेत्रों की सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए बजट में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ मामला उठाया जाएगा ताकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के रखरखाव के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध हो सके । यह बात आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सड़क सीमा संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में पांच राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं जिनकी लम्बाई 570 किलोमीटर है तथा इनमें से एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग (172 कि.मी. लम्बा तांदी से संसारी नाला) सैद्धान्तिक तौर पर सड़क सीमा संगठन के अधीन है। ये सभी उच्चमार्ग सामरिक तथा विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों के लिए सम्पर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग विभिन्न राजमार्गो को भी जोड़ते हैं जिनका रख-रखाव लोक निर्माण विभाग करता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सड़कें बर्फबारी के कारण अक्सर खराब हो जाती हैं तथा इनकी लगातार मुरम्मत तथा रख-रखाव की आवश्यकता रहती है। उन्होंने कहा कि इनके रखरखाव के लिए पर्याप्त निधि की आवश्यकता रहती है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार इन सड़कों पर बने पुलों की भी जल्द मुरम्मत तथा रखरखाव की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को रोहतांग सुरंग के कार्य को नवम्बर माह तक पूरा करने का आग्रह किया ताकि वर्ष भर लाहौल घाटी से सड़क सम्पर्क बना रहे। कृषि एवं जनजातीय विकास मंत्री डा. रामलाल मार्कण्डा ने सीमा सड़क संगठन के अधीन आने वाली सड़कों के रखरखाव पर चिंता व्यक्त की तथा अधिकारियों को निर्धारित सीमावधि में मुरम्मत कार्य पूरा करने का आग्रह किया ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ले. जनरल हरपाल सिंह, अतिविशिष्ट सेवा मैडल, विशिष्ट सेवा मैडल ने मुख्यमंत्री को रोहतांग सुरंग का समय पर निर्माण एवं अन्य सड़क सुधार कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। समदो-काजा-ग्राम्फु सड़क की सामरिक महत्ता के दृष्टिगत इसके सुधार को तेजी से प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी, दीपक परियोजना मुख्य अभियन्ता ब्रिगेडियर डी.के. त्यागी, सेवा मैडल, उपायुक्त कुल्लू डा. रीचा वर्मा, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता आर.के. वर्मा, स्टाफ अधिकारी लै. कर्नल दुष्यन्त पाटिल, लै. कर्नल रोहित जालवी तथा अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बच्चों से यौन शोषण मामले में शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, गाइडलाइन जारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्कूलों में बच्चों से होने वाले यौन शोषण के मामले दबाने वाले शिक्षकों को छह माह से एक साल तक की जेल होगी। यौन शोषण करने वालों के साथ-साथ अब इन मामलों को दबाने वालों के खिलाफ भी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों सहित बीईईओ और सीएचटी को पोक्सो एक्ट की गाइडलाइन भेज दी है। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि यौन शोषण का मामला ध्यान में आते ही पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाए। शिक्षा निदेशालय के ध्यान में मामला लाया जाए। बच्चों और अभिभावकों को भी यौन शोषण के प्रति जागरूक किया जाए। जिलों को जारी पत्र में कहा गया है कि यौन शोषण के मामले ध्यान में आते ही विशेष ज्यूविनाइल पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाए। निदेशक रोहित जम्वाल ने बताया कि यौन शोषण के मामलों में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट के सेक्शन 19 और 20 में स्पष्ट किया गया है कि अगर स्कूल में सामने आए यौन शोषण की जानकारी पुलिस को नहीं दी जाती है तो स्थानीय स्कूल के संबंधित शिक्षक और प्रभारी को छह माह से लेकर एक साल की जेल और जुर्माना होगा। उन्होंने कहा कि जागरूक करने के लिए स्कूलों में प्रतिमाह एसएमसी और शिक्षकों की बैठक की जाए। स्कूलों में मामलों की शिकायत करने के लिए चाइल्ड टोल फ्री नंबर 1098 प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। नेशनल कमीशन आफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की वेबसाइट पर जाकर ई बाक्स लिंक में भी शिकायत करने की बच्चों को जानकारी दी जाए।

पर्यटन सीजन में अवकाश के मामले ने पकड़ा तूल शनिवार को छुट्टी के विरोध में उतरी उद्घोष संस्था

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ज़िला प्रशासन ने शिमला में पर्यटकों की सुविधा एवं यातायात जाम से बचने के लिए शनिवार को शिमला के स्कूलों में बच्चों को छुट्टी करने का निर्णय लिया है जिसका उद्घोष संस्था ने विरोध किया है। ज़िला प्रशासन यदि जाम से निपटने में सक्षम नहीं है तो इसका कोई और उपाय भी निकाला जा सकता है। बाहरी पर्यटकों की सुविधा के लिए शिमला के स्थानीय निवासियों के साथ प्रशासन हमेशा ही भेदभाव का रवैया अपनाती है तथा स्थानीय लोगों को ही समझौता करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई इससे बाधित हो रही है तथा इतनी भारी-भरकम फीस को चुकाने के बाद शनिवार की छुट्टियां करना कितना वाज़िब है? अभिभावक पहले ही फीस और स्कूल के अन्य खर्चों से बोझ तले दबे हैं उस पर प्रशासन का पर्यटकों की सुविधा को बच्चों की पढ़ाई से समझौता करवाना उचित निर्णय नहीं कहा जा सकता है।

पर्यटकों की गाड़ियों को बाईपास पर रोक कर वैकल्पिक व्यवस्था करने की ओर प्रशासन को ध्यान देना होगा । संस्था के चेयरमैन हेम राज चौहान ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई का ये समय बहुत कीमती है तथा इस प्रकार शनिवार को अवकाश घोषित करने के निर्णय का संस्था विरोध करती है। प्रशासन को स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे पूर्व भी जब पानी के लिए शिमला तरस रहा था तो पर्यटकों के लिए होटलों में पानी की समुचित व्यवस्था बनाने के लिए तो उचित कदम उठाए गए थे और लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। अब पर्यटकों की तादात बढ़ी तो स्कूल में शनिवार को अवकाश का निर्णय बच्चों की पढ़ाई और अभिभावकों के साथ अन्याय है। संस्था ज़िलाधीश अमित कश्यप से अपील करती है कि जाम की समस्या के लिए वैकल्पिक माध्यम को चुने न कि बच्चों की कक्षाओं और पढ़ाई को बाधित कर पर्यटकों की सुविधा का ही ध्यान रखें ।

किन्नौर में चट्टानों के गिरने से नौ घंटे बंद रहा एनएच, एक की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ से पांच किलोमीटर की दूरी पर एनएच-5 रल्ली के पास भारी चट्टानों के गिरने से करीब नौ घंटे बंद रहा। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर रल्ली नामक स्थान पर अचानक पहाड़ी से भारी-भरकम चट्टानें गिरी गई ।

इससे रिकांगपिओ से पूह ब्लहक ,स्पीति घाटी और शिमला के लिए बसों सहित अन्य वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। इस दौरान मार्ग के दोनों ओर छोटे व बड़े वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।

सैकड़ों स्थानीय और पर्यटक वाहन फंसे रहे। हालांकि शाम करीब सात बजे एनएच प्राधिकरण ने मार्ग को बहाल कर दिया। अधिशाषी अभियंता एनएच प्रकाश नेगी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बड़ी चट्टानें गिरने से मार्ग अवरूद्ध हो गया था ।

शिक्षा मन्त्री ने किया संजौली महाविद्यालय की वेबसाईट का शुभारम्भ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिक्षा, विधि एवं संसदीय मामले मन्त्री सुरेश भाद्वाज ने बीते सप्ताह उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र राजकीय महाविद्यालय संजौली की नई वेबसाईट का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर संजौली महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. सी.बी मेहत्ता, शिक्षक वर्ग और विद्यार्थी सदस्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वेबसाईट के शुरू होने से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। इस वेबसाईट के माध्यम से एक विद्यार्थी एक से ज्यादा फार्म भी भर सकता है और एक फार्म भरने के पश्चात् उसे ऑनलाइन अपडेट करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि संजौली महाविद्यालय विद्यार्थियों को कैशलैस और पेपर-लैस सुविधा प्रदान करने वाला प्रदेश का पहला कॉलेज है। विद्यार्थी अपनी फीस इस वेबसाईट के माध्यम से एडीएफसी के पेमेंट गेटवे से जमा कर पाएंगे।

सफाई कर्मचारियों के लिए लागू विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के छः दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजीभाई जाला ने यहां मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में सफाई कर्मचारियों के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में चर्चा की गई। बैठक में 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पनुर्वास अधिनियम-2013' को लागू करने के बारे में समीक्षा की गई।

उन्होंने राज्य सरकार को राज्य के अन्तर्गत आने वाली सभी नगर पालिकाओं में रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के पदों को शीघ्र भरने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पनुर्वास अधिनियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि करूणामूलक आधार पर सफाई कर्मचारियां की नियुक्ति के लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। मनहर वालजीभाई जाला ने राज्य की सभी नगर पालिकाओं में सैप्टिक टैंकों की सफाई एवं डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के लिए सकिंग तथा जैटिंग मशीनों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हिमाचल में राज्य स्तरीय सफाई कर्मचारी समिति का गठन प्राथमिकता के आधार पर करवाना चाहिए, जिससे अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने राज्य एवं जिला स्तर पर अनुश्रवण समितियों के गठन का सुझाव भी दिया, जिससे समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया जा सके। मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी भाग में हाथ से मैला नही ढोया जाता तथा सफाई कर्मचारियों को गम बूटस, दस्ताने और फेस-मास्क जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि यदि आउटसोर्स एजेंसियों की ओर से सफाई कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य वित्तीय लाभों में कोई अनियमितता हो रही हो तो उसकी जांच की जाए तथा सफाई कर्मचारियों को पे-स्लिप भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए तरल कचरे को उठाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बैग उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम को जागरूकता शिविर आयोजित करवाने के लिए कहा जिनके माध्यम से सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए लागू की गई योजनाओं की जानकारी दी जा सके।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़
हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें। द रीव टाइम्स, दूरभाष : 9418404334, Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण, इस जैल से होगा उपचार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

आंत और पेट का कैंसर अब जटिल नहीं रहेगा। एक जैल के माध्यम से इस रोग का उपचार किया जा सकेगा। जैल में दवा रहेगी, जिसका पीएच परिवर्तन के अनुसार खुद ही रिसाव होता रहेगा। ट्यूमर के बढ़ने की स्थिति में दवा निरंतर रिलीज होती रहेगी।

तर्क दिया जा रहा है कि ट्यूमर के बढ़ने पर दवा रिलीज नहीं हो पाती है, जिससे पीएच परिवर्तन नहीं होता है। शूलिनी विश्वविद्यालय में चेतना वर्मा, डॉ. पूनम नेगी और डॉ. दीपक पठानिया ने बताया कि पिछले साल 21 नवंबर को प्रयास शुरू किए थे, जो अब सिरे चढ़े हैं। शोध से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी लंबी मेहनत का नतीजा है जो दुनिया भर में कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए उम्मीद की एक किरण साबित होगी। विश्व कैंसर अनुसंधान कोष के 2018 के आंकड़ों के अनुसार, कोलोरेक्टल कैंसर यानी पेट या मलाशय का कैंसर 2018 में दुनिया भर में तीसरा सबसे आम कैंसर है, जिसमें 18 लाख से अधिक नए मामले हैं। कैंसर विरोधी दवाओं में से अधिकांश विषाक्त हैं। एक विशेष स्तर से परे उच्च खुराक संभव नहीं है।

परिणामस्वरूप, रोगी का उपचार धीमा हो जाता है। इसके अलावा, कीमोथैरेपी में गैर-लक्षित दवा वितरण के कारण शरीर में दवाओं का अंधाधुंध वितरण अभी भी बीमारी के लिए मौजूदा उपचारों की एक और सीमा है।

शोध का नेतृत्व कर रहीं डॉ. पूनम नेगी ने कहा कि एंटीसेंसर दवा वितरण प्रणाली का ढेर मौजूद हैं, जिसने स्वस्थ ऊतकों और ठोस ट्यूमर के बीच मौजूद पीएच के मामूली अंतर का फायदा उठाया है।

इस शोध में स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पूनम नेगी, पीएचडी छात्रा चेतना, जम्मू-कश्मीर से डॉ. दीपक पठानिया, प्रो. भुवनेश गुप्ता शामिल हैं।

दुनिया को बड़े खतरे से बचाने में मिलेगी मदद

कैंसर सबसे जटिल बीमारियों में से एक है और दुनिया भर में मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार 2030 तक वैश्विक कैंसर मृत्यु दर 45 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत होने की आशंका है।

कैंसर का सटीक कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, जबकि दुनिया भर के डॉक्टर और शोधकर्ता इसके इलाज को खोजने और मौजूदा तरीकों और उपचारों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

डीसी ने दिखाई राह, पत्तों से कैसे बनाए जा सकते हैं नोट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

हिमाचल में थर्मोकोल से बने कप-प्लेट और डोने पर प्रतिबंध लगा तो उपायुक्त सिरमौर ने उनका विकल्प तलाश लिया। उन्होंने महिलाओं को सिखाया कि कैसे पत्तों से भी नोट कमाए जा सकते हैं।

उन्होंने सबसे पहले उन्हें पत्तल उद्योग से जुड़ने को प्रेरित किया। उन्हें मशीनों पर काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया।

उसके बाद डीआरडीए के वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सिरमौर के संगड़ाह, थाना कसोगा और सतौन में पत्तल बनाने की मशीनें लगाने में सहयोग किया। आज 100 के करीब महिलाएं पत्तल बनाने का रोजगार पा चुकी हैं।

अब तक वे लाखों की कमाई कर चुकी हैं। सिरमौर में रोजाना दस हजार से अधिक पत्तलों का उत्पादन होता है। जिला इसमें सूबे में अव्वल है।

स्मृति चिह्न की जगह देते हैं पौधा

सिरमौर जिले में सरकारी समारोह में सम्मान के रूप में अब मोमेंटो नहीं पौधे दिए जाते हैं। वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस से इसका आगाज किया गया था। तब से अब तक लगभग 20 हजार पौधे विभिन्न स्थानों पर बांटे गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों और स्कूलों में भी ऐसे पौधे दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भी प्रशासन की ओर से बेटी के जन्म पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के साथ एक-एक पौधा दिया जा रहा है। यह पौधा माता-पिता बेटी के नाम पर रोप रहे हैं।

कन्या स्कूल का ग्रीन आर्मी इको क्लब प्रदेश भर में द्वितीय

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

पर्यावरण संरक्षण में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के चलते राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन के ग्रीन आर्मी ईको क्लब को शिमला में हुए राज्य स्तरीय समारोह में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार स्वरूप क्लब को 20 हजार रुपये भी मिले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला के पीटर हॉफ में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

इसमें प्रदेश के चुनिंदा लोगों, संगठनों एवं क्लबों को पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया। इस दौरान राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन के ग्रीन आर्मी ईको क्लब को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया।

प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान और विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने ग्रीन आर्मी ईको क्लब के प्रभारी बाबूराम शर्मा, निशा बंसल एव, छात्राओं प्रतिभा व पूजा को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी व 20 हजार रुपये का चेक देकर पुरस्कृत किया।

क्लब प्रभारी बाबूराम शर्मा और निशा बंसल ने इस सफलता का श्रेय स्कूल की प्रधानाचार्या मीरा बंसल एवं शिक्षकों को दिया। उधर, स्कूल की प्रधानाचार्या मीरा बंसल ने इस उपलब्धि के लिए क्लब के शिक्षकों और छात्राओं को बधाई दी है।

अग्निकांड में एक दर्जन झुग्गियां राख

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

पुराना होशियार रोड पर 4 जून को अग्निकांड में प्रवासी परिवारों के लोगों की एक दर्जन झुग्गियां जलकर राख हो गई। पीड़ित परिवारों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। अग्निकांड में पीड़ित परिवारों का रहने, खाने व पहनने के सामान सहित आभूषण राख हो गए। दमकल विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार होशियारपुर रोड पर झुग्गियों में रह रहे प्रवासी परिवारों हुसैन, फतेहगन, रसीद, अहमद, लजीद व गुलाब मोहम्मद की 12 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। पीड़ितों ने बताया कि इस घटना में उनके आभूषण, गैस, कूलर, पंखा, खाने-पीने का सारा सामान, बर्तन, कपड़े आग की भेंट चढ़ गए। वहीं, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। वहीं, दमकल विभाग के अधिकारी नितिन धीमान ने बताया कि पीड़ित परिवारों को करीब 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। घटना की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। सदर ऊना के होशियारपुर रोड सहित अरनियाला, लोअर कोटला और कोटला कलां में भी झाड़ियों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। दमकल विभाग के अधिकारी विनोद धीमान ने बताया कि विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू कर लिया। अरनिलाया में आग से आवासीय क्षेत्र के घरों और कोटला कलां में पशुशाला को बचाया गया है। अन्यथा लाखों का नुकसान हो सकता था।

3.45 लाख लेकर ठेकेदार फरार, केस दर्ज

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

क्षेत्र के एक ईंट भट्टे के मालिक से ठेकेदार लेबर सप्लाई के नाम पर 3.45 लाख लेकर फरार हो गया। इसकी शिकायत भट्टा मालिक ने पुलिस थाना ऊना में दर्ज करवाई है। ऐसे में न तो भट्टा मालिक को काम करने के लिए लेबर मिली न ही ठेकेदार को दी राशि। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि ठेकेदार उससे काम करवाने के लिए लेबर लाने के लिए करीब साढ़े तीन लाख की राशि ले गया। न ही पीड़ित को काम करने के लिए ठेकेदार को लेबर मिली और न ही ठेकेदार को दिया हुआ पैसा। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार राकेश पुरी निवासी आदर्श नगर ने पुलिस थाना ऊना में शिकायत दर्ज करवाई है कि ठेकेदार गौबर्धन निवासी छतीसगढ़ हाल निवासी झंबर ने उससे 3.45 लाख की राशि ली थी। पुलिस ने पीड़ित राकेश पुरी की शिकायत के आधार पर आरोपी गोवर्धन निवासी छतीसगढ़ हाल निवासी झंबर के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

पेयजल स्कीमें सूखीं, 35 परियोजनाओं में 50 फीसदी घटा पानी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

मौसम की मार का असर अब सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की स्कीमों पर पड़ना शुरू हो चुका है। लोगों में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। आलम यह है कि दिन - प्रतिदिन बढ़ रही तपिश से विभाग की 35 स्कीमों के स्रोत में पानी की गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे ये स्कीमें सूखने की कगार पर हैं।

यदि गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो स्कीमें बिल्कुल सूख जाएंगी। इन स्कीमों में 50 प्रतिशत पानी की गिरावट आ चुकी है। इससे धर्मपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में पानी की होने वाली कमी को लेकर लोगों को तैयार रहना होगा। हालांकि, अभी स्रोत में पानी की कमी के कारण कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आई है। लेकिन स्कीमों में आई गिरावट को लेकर विभाग ने स्कीमों को हैंडपंप और किसी दूसरी जगह से इंटरलिंक किया है।

जानकारी के अनुसार अभी कोई बड़ी बाधा पानी की आपूर्ति को लेकर सामने नहीं आ रही है। विभाग ने स्रोतों में आई गिरावट के चलते लोगों को पानी का दुरुपयोग न करने का आह्वान किया है। सोलन खंड में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की कुल 374 स्कीमें हैं। इनमें से 317 स्कीमें पेयजल और 56 स्कीमें सिंचाई की शामिल हैं। इन स्कीमों के जरिये लोगों को घर-द्वार पर पानी की आपूर्ति की जाती है।

गर्मी के प्रकोप से अब कुछ स्कीमों में पानी का जल स्तर घट चुका है। पिछले वर्ष भी गर्मियों के मौसम में स्कीमों के हांफने से कंडाघाट व धर्मपुर के कुछ हिस्सों में सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने पानी के टैंकरों से लोगों को पानी की सप्लाई की थी। उस समय 6-7 जगहों पर पानी की भारी कमी आ चुकी थी। इसे हल करने के लिए विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता के मुताबिक 5 जून तक 35 स्कीमों में पानी का जलस्तर घट कर 50 प्रतिशत घट चुका है।

ये सभी स्कीमें धर्मपुर क्षेत्र के आसपास की हैं। उन्होंने बताया कि पानी की कमी को लेकर स्कीमों को हैंड पंप या अन्य जगहों से इंटरलिंक किया है। यदि पानी की ज्यादा समस्या सामने आती है तो सरकार की स्वीकृति से टैंकरों के साथ पानी की सप्लाई का प्रावधान रहता है।

अप्पर बाजार में 16 बुलेट कैमरे रखेंगे निगरानी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

सोलन के अपर बाजार की सुरक्षा के लिए जल्द ही कैमरे करेंगे। व्यापार मंडल ने कैमरों को लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। जिससे शहर में हो रही हर प्रकार की गतिविधि की निगरानी रखी जाएगी। कैमरे लगाने के लिए तारों व डीवीआर सिस्टम लगाने का काम शुरू हो चुका है। यही नहीं शहर में आयोजित होने वाले शूलिनी मेले से पहले कैमरों को स्थापित कर दिया जाएगा। गौर रहे कि बाजार में पहले भी कैमरों को लगाया गया था लेकिन ने लंबे अरसे से खराब पड़े थे। जिससे किसी भी समय कोई घटना होने का डर बना रहता था। यही नहीं रात को चोरी की घटनाओं पर नजर रखना भी मुश्किल था। चोरी होने के बाद साक्ष्य भी नहीं मिल पा रहे थे। अपर बाजार में व्यापार मंडल 3 लाख रुपये की लागत से 16 बुलेट कैमरे लगा रहा है। यह कैमरा नाइट विजन होंगे। जिसमें रात को होने वाली प्रत्येक गतिविधि भी साफ दिखाई देगी। इसी के साथ यह फुल एचडी कैमरा हैं। जिसमें पावर बैकअप भी रहेगा, जो लाइट चले जाने पर भी पूरा काम करेंगे। कैमरों में बेहतर क्वालिटी की आर्मड वायर लगाई जा रही है, जिसे बंदर भी नही काट पाएंगे। कैमरों की देखरेख भी व्यापार मंडल के पास रहेगी। कैमरे अहनलाइन काम करेंगे जिसकी सर्विलांस एसपी अहफिस, मालरोड व पुलिस चौकी में रहेगी।

म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लगाया

अपर बाजार एसोसिएशन के प्रधान गिरीश साहनी ने बताया कि बुलेट कैमरों को लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए ३२ चौनल वाला डीवीआर सिस्टम लगाया गया है। उन्होंने बताया कि शूलिनी मेले से पहले कैमरों को लगा दिया जाएगा। अपर बाजार में बैठे कारोबारियों और आने वाले लोगों को अब सुबह और शाम धार्मिक व देश भक्ति के मधुर गीतों की धुन भी सुनाई देगी। जिसके लिए अपर बाजार एसोसिएशन ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया है।

तीन साल से दो किमी दूर से पानी ढोने को मजबूर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

क्षेत्र की कमरऊ पंचायत के लबराड़ा गांव में 80 लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस गए हैं। उनको चिलचिलाती गर्मी में एक से दो किलोमीटर दूर से पानी ढोने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ग्रामीण दिन में कई-कई बार खड़ी चढ़ाई चढ़कर पानी ढो रहे हैं। इससे उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि ग्रामीण तीन साल से पानी की दिक्कत से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके विभाग उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया है।

क्षेत्रवासी सुरेश शर्मा, खजान सिंह शर्मा, आत्मा राम शर्मा, तुला राम शर्मा, संजय शर्मा, अनिल शर्मा, कमलेश शर्मा, प्रताप शर्मा, मुकेश शर्मा आदि ने कहा कि वे इस समस्या को लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं लेकिन उनको हर बार निराशा ही हाथ लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि वे तीन साल से खड़ी चढ़ाई चढ़ कर पानी ढोने को मजबूर हैं। उनका अधिकतर समय पानी ढोने में ही बीत रहा है। बरसात के दिनों में तो गंदा पानी पीने को विवश हो जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस समस्या को वे कमरऊ में 4 नवंबर 2018 को हुए जनमंच में उठाने लगे थे लेकिन उस समय विभाग के अधिकारियों ने उनको इस समस्या को दो महीने में निपटाने की बात कही थी। इसके चलते इस मुद्दे को जनमंच में नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग ने अभी तक इस ओर कोई पहल नहीं की है। इसका खामियाजा वे सभी भुगत रहे हैं। यहां खजियार उठाऊ पेयजल स्कीम से पानी की सप्लाई होती है। इसके 30 से 40 पाइप खराब हो चुके हैं। इससे तीन सालों से उनको पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीण खड़ी चढ़ाई चढ़कर एक से दो किलोमीटर की दूरी तय कर पीठ पर पानी ढो रहे हैं। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से मांग की है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाए।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

3 दिन में बैंक अकाउंट से 2 लाख निकाल ले गए शातिर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

नगरोटा बगवां उपमंडल के एक स्कूल में कार्यरत कर्मचारी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। कर्मचारी से यह ठगी 4 से 7 मई के बीच हुई, इसका पता कर्मी को तब चला, जब वह बैंक से पैसे निकलवाने के लिए गया। हैरानी की बात है कि कर्मचारी ने न तो किसी व्यक्ति को अपना एटीएम दिया और न ही किसी को कोई ओटीपी आदि बताया। बावजूद इसके उसके बैंक अकाउंट से 4 बार एटीएम से पैसे निकाले गए, जबकि तीन बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिये पैसों को अन्य अकाउंट में ट्रांसफर किया गया।

इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस थाना नगरोटा बगवां में भी ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार नगरोटा बगवां उपमंडल के तहत एक सरकारी स्कूल में कार्यरत खोली (कांगड़ा) निवासी मिलखी राम के बैंक अकाउंट से चार मई को 20 हजार रुपये एटीएम के माध्यम से निकाले गए। इसके बाद चार मई को ही 40 हजार रुपये प्रभु लिंगम गुप्त के खाते में ट्रांसफर हुए। इसके बाद 5 मई को फिर पटना के एक एटीएम से 20 हजार और पदमा कलमाला के खाते में 40 हजार रुपये ट्रांसफर हुए, जबकि 6 मई को फिर से ज्योति देवी के खाते में 39 हजार और पटना के उसी एटीएम से 20 हजार रुपये निकाले गए। वहीं 7 मई को फिर से पटना में एटीएम से 20 रुपये की निकासी हुई। कुल मिलाकर पीड़ित को एक लाख 99 हजार रुपये की चपत लगी।

पीड़ित ने बताया कि उसका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा टांडा में है और उसे उसके खाते से रुपये निकाले जाने का पता उस समय लगा, जब घर के किसी सामाजिक कार्य के लिए पैसे निकालने बैंक गया। इस दौरान बैंक स्टाफ ने उसे उसके खाते में रकम कम होने की बात कही।

उन्होंने बताया कि उसे कभी भी किसी व्यक्ति ने फोन पर उसके एटीएम कार्ड बारे कोई सूचना भी नहीं मांगी। इसके बाद उसने बैंक से डिटेल मांगी, जिसमें यह राशि पटना में निकाली गई बताई गई।

वहीं संबंधित बैंक प्रबंधन ने उसे भरोसा दिलाया है कि उसकी रकम को वापस उसके खाते में डलवाने की कोशिश की जाएगी। पीड़ित के अनुसार वह अपने बेटे की शादी के लिए यह रकम निकालने आया था। उधर, इस बारे में संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि उपभोक्ता की रकम की निकासी पटना (बिहार) से होती रही तथा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले को विजिलेंस के सुपुर्द कर दिया गया है।

आईपीएच विभाग ने थुरल में जब्त की पानी की पाइपें

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

पेयजल का गलत इस्तेमाल करने पर थुरल आईपीएच विभाग ने कई गांवों में छापेमारी की। विभाग की टीम ने इस बीच कई लोगों को नल से पाइपें लगा कर खेतों में सिंचाई करते पकड़ा। सहायक अभियंता बलदेव चौधरी और अतिरिक्त सहायक अभियंता विजय वर्मा की टीम ने इलाके के गांवों में दबिश दी। टीम ने थुरल, भ्रांता, वटाहण, वलोह, साई, मूंढी, रपोटा, घुड, मलेहड, पंजलेहड, हेव, कान्हा, सवां, नौण, नलेहड, भनाड, थाना, सेंदू, चूला आदि गांवों में जाकर अपने खेतों में पीने के पानी का दुरुपयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए सभी प्लास्टिक की पाइपों को अपने कब्जे में ले लिया है।

विभाग के सहायक अभियंता बलदेव चौधरी ने बताया कि विभाग जगह-जगह छापेमारी कर रहा है और जो भी व्यक्ति ऐसे कार्यों में संलिप्त पाया गया, उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न गांवों में छापेमारी कर टीम ने पाइपों को अपने कब्जे में ले लिया है तथा आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

दूषित पानी पीने से बीमार हुए चार गांवों के लोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

उपमंडल बैजनाथ की चार पंचायतों के लोग दूषित पानी पीने से बीमार हो गए हैं। इस दौरान करीब दो दर्जन से अधिक ग्रामीण बुखार व उल्टी-दस्त की चपेट में आ गए, जिनका उपचार उपमंडलीय चिकित्सालय में किया गया। जबकि कुछ लोगों को सेहत में सुधार होने पर घर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार बैजनाथ क्षेत्र के सुकारना, नोहरा, चकोल और सकडी गांव के लोग बुखार की चपेट में आ गए। बीमार व्यक्तियों में प्रिंस, इशु, काजल, नीमा देवी, प्रियंका, काकी देवी, सरोजनी, मीतू, अंशुल, नहक, राकेश आदि शामिल हैं। बुखार आने का मुख्य कारण दूषित पेयजल माना जा रहा है। माहलपट्ट पंचायत के तहत आने वाले इन गांवों को पानी की सप्लाई शीतला चौक के समीप स्थित ढरकू नाले से की जाती है। माहलपट्ट पंचायत के पूर्व पंचायत प्रधान सुनील कुमार का कहना है कि 25 वर्ष पुरानी पेयजल योजना के तहत शीतला चौक में बड़े टैंक का निर्माण हुआ है और नाले से बिना किसी फिल्टर के पानी को सीधे टैंक में डाला गया है। लोगों का कहना है कि हर वर्ष इन दिनों पानी के कारण लोग बीमार हो जाते हैं। कई बार विभाग के समक्ष इस समस्या को रखा गया, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हो सका है। पूर्व पंचायत प्रधान सुनील कुमार ने बताया कि पंचायत घर के समीप स्थित इस योजना के तहत आने वाली पेयजल पाइप से गत दिनों किसी बड़े आकार के कीड़े के पंख निकल थे।

उधर, आईपीएच विभाग के एसडीओ नरेश कुमार ने बताया कि पिछले दिनों पानी को लैब में भेजा गया था और यह सही पाया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही क्षेत्र में ट्यूबवेल की स्थापना की जा रही है।

नगर पंचायत तलाई गृह कर के लिए फिर से करवाएगी सर्वे

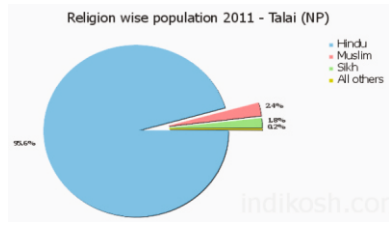

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

नगर पंचायत तलाई में गृह कर वसूली के लिए एक बार फिर से सर्वे किए जाएंगे। इस सर्वे में बचे हुए रिहायषी व व्यावसायिक संस्थानों को रखा जाएगा और उन्हें गृह कर के दायरे में लाया जाएगा। हालांकि वर्तमान में नगर पंचायत ने 5 लाख 17 हजार रुपये गृह कर वसूला है लेकिन अभी भी नगर पंचायत के तहत आने वाले कई क्षेत्र अभी भी गृह कर के दायरे से बाहर बचे हुए हैं। अब नगर पंचायत की आय बढ़ाने के लिए नगर पंचायत फिर से सर्वे करवाने जा रहा है। यह निर्णय नगर पंचायत तलाई की बीते दिनों हुई एक बैठक में लिया गया। इस निर्णय से नए सर्वे के दौरान लाखों रुपये की आय बढ़ने की संभावना वन जाएगी। उधर अध्यक्ष बलदेव स्याल ने बैठक के दौरान नगर पंचायत कर्मचारियों को आदेश दिया है कि गृहकर की अदायगी न करने वालों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिन इसके बाद भी लोग गृह कर अदा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इतना ही नहीं बाजार में दुकानों के आगे जिन दुकानदारों ने अवैध रूप से टीन के शेड डाल रखे हैं उनके खिलाफ 183 के तहत कार्रवाई करने पर चर्चा की गई तथा बाजार में नालियों के ऊपर दुकानदारों द्वारा सजाई गई दुकानदारी को हटाने के लिए एक मुहिम चलाने का निर्णय भी लिया गया। नगरप पंचायत के सातों वार्डों में विकासात्मक कार्यों के लिए भी बैठक में प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें गुरूना झाड़ी मंदिर से आगे नगर पंचायत पार्किंग तक कच्ची सड़क पर पेवर लगाने का भी निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व नगर पंचायत में आऊटसोर्सिंग पर 10 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। बैठक में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष बृजलाल, सरोज धीमान, हरपाल कालिया, रामी देवी, सुनीता देवी, नगर पंचायत के कनिष्ठ अभियाता संजय पठानिया, वरिष्ठ क्लर्क विनोद कुमार, क्लर्क अनिल कुमार उपस्थित थे।

जिले में बढ़ते प्रदूषण से कम हुआ मछली उत्पादन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

जिले में पिछले कुछ सालों से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है जिसका परिणाम है कि गोबिंद सागर में मछलियों का उत्पादन सालदर साल घटता जा रहा है। जबकि जिले में चल रहे सीमेंट उद्योगों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रहा है।

जिले में नेरचौक-कीरतपुर फोरलेन निर्माण के दौरान गोबिंद सागर में जमकर अवैध रूप से मलबा डाला गया है जिसका सीधा असर मछली उत्पादन पर पड़ा है। हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था। कमेटी एसडीएम बिलासपुर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। कमेटी ने जांच में पाया कि फोरलेन निर्माण के दौरान अवैध रूप से की गई डंपिंग से करीब 70 नदी नालों जिसमें गोबिंद सागर भी शामिल है, में जमकर मलबा डाला गया है। इसके बाद संबंधित कंपनियों और विभाग को अवैध रूप से डंप किए गए मलबे को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। यही नहीं नदी नालों में डंप किए गए मलबे के मामले पर एनजीटी दिल्ली में भी सुनवाई चली हुई है। नदी नालों में मलबा डालने से फैले प्रदूषण के कारण सैकड़ों मछुआरों के परिवारों पर भी संकट खड़ा हुआ है।

पालंगरी और मंझोत में बिजली की कम वोल्टेज से लोग परेशान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

नम्होल विद्युत उपमंडल के दयोथ अनुभाग के तहत आने वाले बाल पालंगरी व मंझोत गांव के कई परिवार बिजली की कम वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कई बार विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को भी समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान करवाया जाए।

गांव के करीब दो दर्जन परिवारों को विनायकघाट में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से बिजली की सप्लाई होती है, करीब दो दशक पहले लगे इस ट्रांसफार्मर से सिंगल फेस से इन गांवों को बिजली सप्लाई होती है। इतना समय बीत जाने पर अभी तक इसे थ्री फेस में नहीं बदला गया है। जबकि इस विद्युत लाइन से लगातार विद्युत आपूर्ति की मांग बढ़ रही है।

कम वोल्टेज होने के कारण लोग अपने बोरवेल या अन्य विद्युत उपकरण भी नहीं चला पा रहे हैं। स्योहला पंचायत के पूर्व उपप्रधान गोपाल शर्मा, विजय कुमार, राजेश शर्मा, रोशन लाल, अमरदेव, लेखराम ने विद्युत बोर्ड से उनकी विद्युत लाइन को थ्री फेस में बदलने की गुहार लगाई है।

इस बारे में विद्युत उपमंडल नम्होल के सहायक अभियंता नंदलाल शर्मा ने बताया कि इसको 2019-20 की प्लान में डाला है, स्वीकृति मिलते ही इसे थ्री फेस की लाइन में तब्दील कर दिया जाएगा।

बिझड़ी क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाएं ठप

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

विकास खंड बिझड़ी की आधा दर्जन पंचायतों में बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवाएं बीते एक माह से ठप पड़ी हैं। इससे क्षेत्र की पंचायतों बल्हविहाल, धंगोटा, भैल, समताना आदि में बीएसएनएल की सेवाएं प्रभावित रही हैं। इससे सैकड़ों उपभोक्ता खासे परेशान हैं। जिन उपभोक्ताओं ने अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवाई है, वह भी पछता रहे हैं। पंचायतों में ऑनलाइन कार्य करने में भी काफी दिक्कत आ रही है।

इन इलाकों में लोगों को किसी प्रकार के ऑनलाइन लेन देन करने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं, कार्यालयों का कार्य भी ब्राडबैंड और इंटरनेट सेवाएं ठप होने से प्रभावित हो रहा है। धंगोटा में स्थित सेंट्रल बैंक का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस संदर्भ में एसडीओ बीएसएनएल कार्यालय हमीरपुर रविंद्र कुमार के मुताबिक कि इन इलाकों में समस्या चल रही है। जल्द ही इसे ठीक करवा दिया जाएगा।

कदरयाणा में कबाड़ का स्टोर और चार गाड़ियां अग्निकांड में राख

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

ग्राम पंचायत डिडवीं टिक्कर के तहत पड़ते कदरयाणा गांव में 5 जून की रात को एक कबाड़ के स्टोर में भयंकर आग लग गई। आग से कबाड़ में रखी चार गाड़ियों, दो स्कूटरों समेत प्लास्टिक और रद्दी जल कर राख हो गई। आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले स्टोर के साथ रखी लकड़ी में लगी थी। बहरहाल स्टोर मालिक ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। वहीं, दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है।

मोहम्मद इकबाल कदरयाणा गांव में राहुल ट्रेडिंग प्रॉपर्टी के नाम से कबाड़ का व्यापार करता है। 5 जून रात को वह स्टोर से अपने घर कदरयाणा गांव चला गया। रात करीब साढ़े दस बजे उसे लोगों से स्टोर में आग लगने की सूचना मिली। वहीं, लोगों ने अग्निकांड की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया लेकिन, तब तक सब जलकर राख हो गया। विभाग के अनुसार पीड़ित को करीब 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इस अग्निकांड में कबाड़ में रखीं चार गाड़ियां, दो स्कूटर, प्लास्टिक, गत्ता और रद्दी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं, दमकल विभाग ने दो कबाड़ से भरे ट्रकों, 17 गाड़ियों और साथ लगती दुकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया है।

वहीं डिडवीं टिक्कर के पास कोई हाइड्रेंट या पानी का साधन न होने के कारण विभाग को पांच गाड़ियां जिला मुख्यालय से भरनी पड़ी। इस कारण आग बुझाने में अधिक समय लगा। अगर डिडवीं टिक्कर क्षेत्र में कोई हाइड्रेंट होता तो नुकसान कम हो सकता था।

हरीकेश मीणा ने बतौर डीसी हमीरपुर संभाला कार्यभार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

2012 बैच के आईएएस अधिकारी हरीकेश मीणा ने 4 जून को हमीरपुर जिले के नए उपायुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। हरीकेश मीणा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं। आईएएस काडर में आने से पहले वह राजस्थान काडर के आईएफएस अधिकारी रहे हैं। वह आईएएस काडर में आने के बाद बतौर एसडीएम नालागढ़ रहे। अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में जिला मंडी में सेवाएं दीं। विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग शिमला तथा इसके बाद डेढ़ वर्ष तक चंबा के उपायुक्त रहे। आईआईटी कानपुर में भी कार्यरत रहे। प्राईवेट सेक्टर में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि जिले में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि, प्रत्येक पात्र व्यक्ति लाभान्वित हो सके। जिला में ग्रामीण विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्रशासन में दक्षता लाई जाएगी तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से लोगों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मरीजों के लिए छोटा पड़ गया कुल्लू अस्पताल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में गर्मियों के चलते मरीजों की तादाद अधिक बढ़ गई है। ऐसे में यहां पर मरीजों के लिए वार्ड में ही जगह कम हो गई है। मरीजों को कुल्लू अस्पताल में गैलरी में बैड लगाकर उपचार करवाना पड़ रहा है। अस्पताल के मेडिसन और अन्य वार्ड में दो दर्जन से अधिक मरीजों का उपचार गैलरी में चल रहा है। कुछ मरीजों को नए अस्पताल वाली बिल्डिंग की गैलरी में रखा गया है। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 300 बैड की क्षमता है।

जिले में भी इन दिनों गर्मियों का असर, बदलते मौसम के प्रभाव के कारण मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। सबसे अधिक मरीज मेडिकल वार्ड में हैं। इसके अलावा सर्जरी में भी मरीजों बढ़े हैं। अस्पताल में कम मरीजों को रखने की क्षमता है। संख्या बढ़ने से प्रबंधन के लिए मरीजों को रखना मुश्किल हो रहा। अगर मरीजों की संख्या बढ़ने का यह क्रम लगातार बढ़ता रहा तो अस्पताल प्रबंधन के लिए यह चुनौती बन जाएगी। बताया जा रहा है मरीज अधिक होने से डॉक्टर को राउंड करने में काफी लंबा वक्त लग रहा है। गौर रहे कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में लाहौल - स्पीति, चंबा जिला के पांगी, मंडी जिला के सीमांत क्षेत्रों से भी लोग उपचार को आते हैं। लाहौल-स्पीति के लिए सड़कें बहाल होने से यहां पर मरीज उपचार को आ रहे हैं।

दूसरी ओर गैलरी में उपचार करवाए जाने से मरीजों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर, इस संबंध में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के चिकित्सा अधीक्षक डह. भारत भूषण कटोच ने कहा कि गर्मियों के दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है।

16 हजार फीट ऊंचा बारालाचा दर्रा बहाल, मनाली-लेह मार्ग पर जल्द दौड़ेंगे वाहन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

छह महीने से बंद मनाली-लेह सामरिक मार्ग दो दिन बाद बहाल हो जाएगा। 485 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 13050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा के बाद अब 15000 फीट ऊंचे बारालाचा दर्रा से भी बर्फ को हटा दिया गया है।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का दावा है कि दो दिन बाद इस रूट पर सेना के वाहनों की आवाजाही शुरू होगी। बीआरओ ने अनौपचारिक तौर पर लेह-हिमाचल की सीमा को आपस में जोड़ दिया है लेकिन सड़क से पूरी तरह बर्फ नहीं हटाया जा सका है। दो दिन बाद ही इस मार्ग के खुलने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इसके बाद सबसे पहले बाहंग और दालंग ट्रांजिट कैंप से सेना के वाहनों को लेह की तरफ रवाना किया जाएगा। पहले दिन किसी भी निजी वाहन को आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। पिछले साल 18 मई को मनाली-लेह मार्ग खुल गया था जबकि 23 मई से एचआरटीसी की बस सेवा शुरू हुई। इस बार पिछले साल की तुलना मनाली-लेह मार्ग करीब 20 दिन देरी से खुलने जा रहा है। हजारों सैलानी मार्ग खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बुधवार को बीआरओ के महा निदेशक ने भी बारालाचा दर्रे का दौरा कर बर्फ हटाने के काम का निरीक्षण किया।

भूस्खलन से तीन गांवों को खतरा, रास्ते हो गए बंद

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चम्बा

चुराह उपमंडल के तहत ग्राम पंचातय चरोड़ी के ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भूस्खलन से पंचायत के तीन गांवों को हुए खतरे के बारे में अवगत करवाया। उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि इस बारे उचित प्रयास किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कोचू राम, नरैण सिंह, भाग सिंह, राकेश कुमार, गोपाल सिंह, राजू राम, तेज सिंह, हेमराज, रमेश कुमार और भूरी सिंह ने बताया कि गांव दालुई, छजयाणी और पद्दरी में भूस्खलन के चलते नुकसान हो रहा है।

इस कारण ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि भूस्खलन के कारण गांवों को जोड़ने वाला रास्ता भी बंद है। इस बारे वे पंचायत को भी अवगत करवा चुके है। लेकिन अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं।

यह कार्य पंचायत को वन विभाग से करवाया जाना है। इसके लिए ग्राम सभा की ओर से प्रस्ताव भी डाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्य 2018-19 में मंजूर हो चुका है। लेकिन बीते दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कार्य लटक गया है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस कार्य को जल्द करवाया जाए। जिससे उन्हें परेशानी न हो।

108 एंबुलेंस में नहीं मिली दवाइयां और जरुरी उपकरण

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चम्बा

जिले में चलने वाली 108 एंबुलेंस वाहनों में बड़ी खामियां सामने आई है। समय पर एंबुलेंस न मिलने से नवजात की मौत के मामले में बीते दिनों मुख्य चिकित्सा अधिकारी के औचक निरीक्षण में बात सामने आई है। जांच पाया गया कि कई एंबुलेंस वाहनों में न ही जरूरी दवाइयां है और नहीं जरूरी उपकरण।

इससे साफ है कि 108 एंबुलेंस वाहनों में मरीजों को सुविधाएं देने के नाम पर उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जल्द ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को भेजेंगे। गौरतलब हो कि बार - बार 108 एंबुलेंसो को लेकर मिल रही शिकायतों के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकरी व स्वास्थ्य अधिकारी ने एंबुलेंसो का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एंबुलेंस के अंदर कई खामियां पाई गई। जिसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है।

इसके साथ ही एसडीएम चंबा ने भी मेडिकल कॉलेज में जाकर एंबुलेंस वाहनों से संबंधित रिकॉर्ड को तलब किया। एंबुलेंस के भीतर मरीज की आवश्यकता अनुसार जो दवाइयां होनी चाहिए, वह एंबुलेंस में मौजूद नहीं थी। इतना ही नहीं जीवन रक्षा के लिए जरूरी यंत्र लिफाफे में बंद पड़े थे। जिनका इस्तेमाल शायद ही कभी किया गया हो।

पांगी से आई एंबुलेंस की हालत खस्ता, सुविधाएं भी नहीं

पांगी से मरीज को लेकर चंबा पहुंची एंबुलेंस का जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण किया। तो उसके अंदर दवाई, जरूरी उपकरण कुछ भी नहीं पाया गया। खाली गाड़ी में मरीजों को ढोया जा रहा है। इसके अलावा एंबुलेंस में मरीज को लेटाने वाली सीट के कवर फट चुके थे। अगर इमरजेंसी में मरीज को किसी दवा या अन्य जीवन रक्षा उपकरण की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी कोई सुविधा पांगी की एंबुलेंस में मौजूद नहीं थी।

हालांकि पांगी जिला का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। लेकिन एंबुलेंस संचालक कंपनी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। एंबुलेंस कर्मचारियों से जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यूनिफार्म के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 के बाद उन्हें एक बार भी वर्दी नहीं दी गई है।

इसके अलावा एंबुलेंस कर्मियों के गले में कोई आई कार्ड भी नहीं था। जिससे उनकी पद की पहचान हो सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि चंबा में एंबुलेंस वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया है। एक एंबुलेंस में दवाई और अन्य कोई भी उपकरण नहीं था। जबकि दूसरी एंबुलेंस में भी कई खामियां पाई गई है। इसकी रिपोर्ट बना दी गई है। जिसे स्वास्थ्य निदेशक को भेजा जाएगा।

रेशम का उचित दाम न मिलने पर विभाग ने रद्द कर दिया टेंडर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

रेशम के उचित दाम न मिलने के कारण विभाग ने टेंडर रद्द कर दिए हैं। मई महीना बीत जाने के बाद भी रेशम पालकों से रेशम की पैदावार नहीं उठाई गई है। कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान झेलने की चिंता सता रही है। अगर फसल को जल्द नहीं उठाया गया तो फिर बरसात में यह खराब हो जाएगी।

धर्मपुर की प्रगतिशील रेशम पालक समिति ने बैठक का आयोजन कर फसल न खरीदे जाने पर चिंता जताई। सदस्यों ने कहा कि पिछली बार 30 मई तक फसल खरीदी जा चुकी थी। रेशमपालकों को 960 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से कोकून के दाम मिले थे।

इस साल अभी तक फसल को खरीदने की कवायद ही शुरू हो पाई है। विभाग ने टेंडर में कम रेट मिलने के कारण टेंडर को रद्द कर दिया है। ठेकेदारों की ओर से सिर्फ 600 रुपये के हिसाब से दाम दिए जा रहे हैं। रेशम पालकों ने सरकार और विभाग से आग्रह किया है कि उनको फसल का उचित दाम दिलाया जाए।

समिति के चेयरमैन चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने सरकार और विभाग से मांग उठाई कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित दाम दिलवाया जाए। उनकी फसल को मंडी तक समय से पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें नुकसान न उठाना पड़े।

अचानक भड़की आग से 18 झुग्गियां जलकर राख, लाखों रुपये का नुकसान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिला मुख्यालय के पास बीते दिनों लालसिंगी गांव में अग्निकांड से प्रवासी मजदूरों की 18 झुग्गियां जलकर स्वाह हो गईं। इससे झुग्गियों में रखा कीमती सामान भी जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार को करीब एक लाख रुपये का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार दोपहर लालसिंगी में अचानक झुग्गियों में आग भड़क गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने 18 झुग्गियों को चपेट में ले लिया।

आग की लपटें देख लोगों में अफरा - तफरी मच गई

आग की लपटें देख लोगों में अफरा-तफरी मच गई। झुग्गियों में आग लगने से इसमें रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। फायर ब्रिगेड ऊना के प्रभारी नितिन कुमार ने कहा कि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि लालसिंगी में 18 झुग्गियां जलने से करीब 90 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान है।

खुले में कूड़ा फेंकने और जलाने पर नप चंबा को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोटिस

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चम्बा

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खुले में कूड़ा जलाने को लेकर नगर परिषद चंबा को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में नगर परिषद को हिदायत दी गई है कि खुले में कूड़ा जलाने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुले में कूड़ा जलाने से वातावरण दूषित हो रहा है। इसका सीधा प्रभाव आम लोगों की सेहत पर पड़ेगा। पिछले कुछेक दिनों से सुल्तानपुर, आईटीआई मार्ग, सरोथा नाला, परेल घार, सरोल, कसाकड़ा, बालू, हरदासपुरा और करियां समेत अन्य क्षेत्रों में नगर परिषद के ठेकेदार कूड़े को खुले में ठिकाने लगा रहे हैं। बाद में रात के अंधेरे में कूड़े को आग लगाकर निष्पादित किया जा रहा है। इससे ठेकेदार को अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। मगर लोगों की सेहत पर प्रदूषित धुएं का बुरा असर हो रहा है। जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ध्यान में यह मामला आया तो बोर्ड के अधिकारी ने तुरंत नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नप को नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन नगर परिषद अपनी कारगुजारी को बंद करने का नाम नहीं ले रही है। शहर का सारा कूड़ा कर्कट गाड़ियों में भरकर सुल्तानपुर हेलीपैड, आइटीआई मार्ग, शनि मंदिर, सरोल में नदी व खड्डों में फेंका जा रहा है।

जिससे नदी व नालों का पानी भी दूषित हो रहा है। कई इलाकों के लोग नदी नालों का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पानी में गंदा कूड़ा कर्कट मिलने से पानी दूषित हो रहा है। जिसे पीने वाले लोगों की सेहत भी खराब हो सकती है। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नप को नोटिस जारी किया है।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि खुले में कूड़ा जलाने और फेंकने को लेकर नप को नोटिस जारी किया गया है। कूड़ा फेंकने वालों पर बोर्ड पूरी नजर रखे हुए है। पकड़े जाने पर वाहन चालकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चार माह के अंतराल के बाद आईपीएच विभाग भेज रहा पानी के बिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चम्बा

शहरी क्षेत्र में पानी का बिल नियमित रूप से हर माह नहीं भेजा जा रहा है। इसके चतले उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं ने बताया कि विभाग एक साथ तीन महीनों का बिल पिछले काफी समय से भेज रहा था लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर चार माह कर दिया गया है। इसी माह चार माह का बिल एक साथ आया है, जिस कारण उपभोक्ताओं को बिल एक साथ जमा करवाने में समस्या होगी। उपभोक्ताओं का कहना है कि हर माह नियमित रूप से पानी के बिल जारी करने की मांग वे कई बार विभाग से उठा चुके हैं लेकिन आज दिन तक उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं में रोष है।

उपभोक्ताओं रमेश कुमार, सुनील कुमार, भीम सेन, देवी प्रकाश, उत्तम दास, सुभाष कुमार, सुनील कुमार, सतेंद्र सिंह, राकेश कुमार, परस राम, विजय कुमार, नंदलाल, मान सिंह, देवी सिंह, रूपलाल, मदन, राकेश और दुनी चंद ने बताया कि बिजली का बिल विद्युत बोर्ड हर माह भेजता है जिस वजह से उन्हें यह बिल जमा करवाने में आसानी होती है लेकिन, आईपीएच विभाग पानी का बिल तीन से चार माह के बाद भेज रहा है। इससे उन्हें बिल जमा करवाने में कई बार दिक्कत होती है। उन्होंने बताया कि चार माह बाद इकट्ठा बिल आने से बजट भी गड़बड़ा जाता है। उन्होंने आईपीएच विभाग से मांग की है कि जल्द हर माह पानी के बिलों की बिलिंग सुनिश्चित बनाई जाए।

मंडी में बनाया जाए देव माधोराय का मंदिर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

सर्व देवता समिति मंडी की बैठक बीते दिनों को प्रधान शिवपाल की अध्यक्षता में धर्मसभा भवन में हुई। बैठक में कमेटी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। इसमें जिला प्रशासन और सरकार से देव माधोराय का एक भव्य मंदिर बनाने की मांग की गई, ताकि शिवरात्रि के दौरान शोभा यात्रा निकालने में सभी को सुविधा रहे। शिवरात्रि मेले के दौरान कारदारों को होने वाली समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसमें समस्त कारदारों ने अपने-अपने सुझाव दिए। कमेटी के प्रधान ने कहा कि दिन-प्रतिदिन देवी-देवताओं के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था में कमी आ रही है। उन्होंने सरकार से देव सदन के निर्माण को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। देवता कमेटी ने कहा कि जो मंदिर सरकारी भूमि में प्राचीन काल से बने हैं, उस भूमि को देवता के नाम किया जाए। इस मौके पर लेखराज पटियाल, रेवनी राम शर्मा, मनोज, धर्मेंद्र, बुधे राम, बलि राम, गोविंद राम शर्मा, कर्म सिंह, बलवीर, कृष्णा चंद, डुमणू राम सहित अन्य कारदारों ने भाग लिया।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

तलाक देने की प्रक्रिया

तलाक के लिए दाखिल करना एक जबरदस्त प्रक्रिया हो सकती है, खासतौर से क्योंकि इसमें कई जिंदगी का भविष्य शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान करना महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया सुचारू रूप से होती है और आप परिणाम से संतुष्ट हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा कवर हिंदू विवाह के लिए यहां जानकारी ले सकते हैं ।

यदि आपके और आपके पति-पत्नी के बीच चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं, और आप या दोनों ने कानूनी रूप से अलग-अलग तरीके से भाग लेने का फैसला किया है, तो हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के लिए आपके द्वारा दर्ज विकल्पों को सूचीबद्ध करते हैं।

यदि आप और आपके पति दोनों तलाक के लिए तैयार हैं

हिंदू युगल के बीच म्यूचुअल सहमति तलाक धारा 13 बी के तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित है।

जो कहता है- तलाक के डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए एक याचिका दोनों पक्षों द्वारा एक साथ विवाह के लिए जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है, इस आधार पर कि वे एक साल या उससे अधिक अवधि के लिए अलग से रह रहे हैं, कि वे एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं और उन्होंने पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है कि विवाह को भंग किया जाना चाहिए ।

दूसरा, दोनों पक्षों की गति पर उपधारा (1) में उल्लिखित याचिका की प्रस्तुति की तारीख के छह महीने पहले नहीं और उस तारीख के 18 महीने बाद नहीं, अगर याचिका वापस नहीं ली जाती है इस बीच, अदालतों की सुनवाई के बाद अदालत संतुष्ट हो जाएगी और इस तरह की पूछताछ करने के बाद फिट बैठेगी, कि विवाह को समझाया गया है और याचिका में औसत सत्य हैं, तलाक का एक डिक्री शादी को घोषित करने के लिए पास करें डिक्री की तारीख से प्रभाव के साथ भंग किया जाना चाहिए ।

यदि आप या आपका पति तलाक के लिए तैयार हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति तलाक नहीं चाहता है

यदि आप हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाहित हैं, तो आपके पास कानून द्वारा प्रदान किए गए तलाक के लिए कई आधार हैं । यहां हम इस अधिनियम की धारा 13 में उल्लिखित सभी आधारों पर चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने साथी को तलाक देने के लिए अपने मामले का आधार बना सकते हैं ।

आप तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं

- अगर उन लोगों द्वारा सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए जीवित रहने के बारे में नहीं सुना गया है, जो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना होगा, तो वह पार्टी जिंदा थी ।
- अगर शादी के बाद उसके पास किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संभोग होता है ।
- यदि वह आपको क्रूरता से इलाज कर रहा है ।
- यदि उसने याचिका की प्रस्तुति से पहले दो साल से कम समय की निरंतर अवधि के लिए आपको छोड़ दिया हैय
- यदि वह किसी अन्य धर्म में रूपांतरण करके हिंदू बन गया है ।
- यदि वह असुरक्षित मन से पीड़ित है या मानसिक विकार से निरंतर या अंतःक्रियात्मक रूप से पीड़ित है, तो आप उचित रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ रहने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं ।
- यदि आपका पति-पत्नी कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोग से पीड़ित है
- यदि वह एक संवादात्मक रूप में विषयी रोग से पीड़ित है ।
- यदि आपके पति-पत्नी ने किसी धार्मिक आदेश में प्रवेश करके दुनिया को छोड़ दिया है ।

तलाक के लिए फाइल करने के लिए आपके लिए कुछ अतिरिक्त ग्राउंड उपलब्ध हैं

उपर्युक्त आधार पति और पत्नी दोनों के लिए उपलब्ध हैं । हालांकि, कुछ अतिरिक्त आधार हैं जो केवल पत्नी के लिए उपलब्ध हैं । मिसाल के तौर पर, अगर आपके पति को बलात्कार, सोडोमी या पाशविकता का दोषी पाया गया है, तो आप तलाक के लिए पूछ सकते हैं। इसी प्रकार, अगर आपकी शादी १५ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले समझा या समझा नहीं गया था, और आप तलाक लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं।

फाइल कहां करें

तलाक याचिका पारिवारिक अदालत में दायर की जा सकती है, जिसके पास आपके वैवाहिक घर पर अधिकार क्षेत्र है, यानी वह घर जहां आप रहते हैं आखिरी बार पति और पत्नी के रूप में आपकी शादी के बाद या विवाह के दौरान परिवार अदालत में रहते थे। महिलाएं या तो पारिवारिक अदालत में याचिका दायर कर सकती हैं जिनके पास वैवाहिक घर स्थित है या उस इलाके की पारिवारिक अदालत में अधिकार क्षेत्र है जहां वह याचिका दायर करने के समय रह रही है।

तलाक कई रूप ले सकता है। कुछ मामलों में, यह लाने के लिए सुखद और अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन यह भी बहुत जटिल हो सकता है। आप किस नतीजे के परिणाम चाहते हैं?

- क्या आपके पास अपने पति-पत्नी के साथ संपत्ति या अन्य संपत्तियां हैं जो आप विभाजित करने की योजना बना रहे हैं ।
- क्या आपके पति-पत्नी के साथ बच्चे हैं, और क्या आप हिरासत की तलाश करेंगे ।
- अगर आप हिरासत की तलाश में हैं, तो क्या आप अपने पति- पत्नी से बाल समर्थन भी लेंगे
- एक तलाक मिशन कथन बनाने पर विचार करें ताकि आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित कर सकें

अपने तलाक याचिका दायर करने के लिए सही वकील ढूँढना

चाहे आप किस तरह के तलाक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं (म्यूचुअल या प्रतियोगिता), यह महत्वपूर्ण है कि एक सक्षम वकील तलाक प्रक्रिया की बारीकियों के साथ आपको प्रतिनिधित्व-मार्गदर्शन करे।

एक अनुभवी तलाक वकील के साथ परामर्श निर्धारित करें। यहां तक कि प्रतीत होता है कि सीधा तलाक भी जटिल हो सकता है, और एक तलाक वकील आपकी परिस्थितियों के बारे में विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। यहां तक कि यदि आप स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वकील के साथ एक घंटे का परामर्श आपको बेहतर तैयार करने में मदद करेगा।

- अपने लक्ष्यों और वांछित परिणाम के बारे में बात करने के लिए तैयार रहें।
- अपनी संपत्तियों और ऋणों पर एकत्रित दस्तावेज लाओ।
- उन प्रश्नों की एक सूची है जो वकील से पूछने के लिए तैयार आपकी परिस्थिति के लिए विशिष्ट हैं।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर पूछे जा सकते है।

एंग्जायटी डिसॉर्डर : नजरअंदाज न करें इसे

सब गडबड हो गया, अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें..उफ हरदम मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? हममें से ज्यादातर लोगों के मन में कभी न कभी ऐसी बातें चल रही होती हैं। जीवन की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, जब मजबूत दिल वाला इंसान भी चिंतित और भयभीत हो जाता है। मुश्किल हालात में थोडी देर के लिए ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को हमेशा चिंता या डर में जीने की आदत पड जाए तो आगे चलकर यही मनोदशा एंग्जायटी डिसॉर्डर जैसी गंभीर समस्या में बदल सकती है। जब ऐसी नकारात्मक भावनाओं पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण न हो और तमाम कोशिशों के बावजूद छह महीने से ज्यादा लंबे समय तक इसके लक्षण दिखाई दें तो यह समस्या एंग्जायटी डिसहर्डर का रूप धारण कर सकती है।

क्या है मर्ज

हमेशा चिंता, बेचौनी, वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित भविष्य का डर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। हालांकि, हर व्यक्ति में इसके अलग-अलग लक्षण नजर आते हैं, लेकिन स्थायी डर और चिंता लगभग सभी में देखे जाते हैं। अगर ये लक्षण ज्यादा तीव्र न हों तो समय बीतने के साथ समाप्त हो जाते हैं, अन्यथा एंग्जाइटी डिसार्डर की समस्या हो सकती है। इससे व्यक्ति की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित होने लगती है।

क्यों होती है समस्या

आजकल महानगरों की युवा आबादी का एक बडा हिस्सा इस मनोवैज्ञानिक समस्या से जूझ रहा है। दरअसल आधुनिक जीवनशैली में लोगों की व्यस्तता इतनी बढ गई है कि वे हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और उन पर काम का दबाव भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन और आक्रोश बढता जा रहा है । इसके अलावा आधुनिक समाज में हर व्यक्ति अकेला है । किसी के भी पास दूसरे की बातें सुनने की फुर्सत नहीं है । इसलिए अब लोगों में शेयरिंग की भावना खत्म हो रही है। शहरी समाज इतना व्यक्तिवादी और आत्मकेंद्रित हो चुका है कि अब पहले की तरह रिश्तेदारों या पास-पडोस का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रह गया है । लगातार तनाव, अकेलेपन और उदासी में जीने की वजह से ही लोग एंग्जायटी डिसॉर्डर के शिकार हो रहे हैं ।

अध्ययनों के अनुसार गंभीर या लंबे समय तक चलने वाले तनाव की वजह से अनिद्रा की समस्या होती है। इससे मस्तिष्क से निकलने वाले हॉर्मोस के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है, जो एंग्जायटी डिसॉर्डर का कारण बन सकता है। आनुवंशिकता भी इसकी प्रमुख वजह है।

एंग्जायटी डिसॉर्डर के प्रकार

प्रमुख लक्षणों के आधार पर इस मनोवैज्ञानिक समस्या के कई अलग-अलग प्रकार निर्धारित किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं :

जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसॉर्डर : इस समस्या से पीड़ित लोग बेवजह बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। इनकी चिंता का कोई तार्किक आधार नहीं होता। हमेशा चिंता में रहना इनकी आदत होती है। सकारात्मक परिस्थितियों में भी ऐसे लोग चिंतित होने की कोई न कोई वजह ढूंढ लेते हैं।

ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसॉर्डर : इससे पीड़ित लोग लगातार चिंतित या भयभीत रहते हैं। ऐसे में वे कुछ अजीब आदतें विकसित कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को सफाई की सनक हो जाती है और वे साफ-सुथरी चीजों को भी बार-बार धोते-पोछते रहते हैं।

पैनिक डिसॉर्डर : इस समस्या से जूझ रहे लोगों को अकसर ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी सांस रुक रही है या उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे लोगों को बेवजह मौत का भय सताता रहता है ।

सोशल एंग्जाइटी डिसॉर्डर : ऐसी समस्या से पीडित व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में अत्यंत सतर्क रहता है। उसे हरदम ऐसा लगता है कि लोग उसे ही घूर रहे हैं । वह भीड़ वाली जगहों और सामाजिक समारोहों में जाने से बचने की कोशिश करता है क्योंकि ऐसे माहौल में उसे बहुत घबराहट महसूस होती है।

क्या है नुकसान

एंग्जायटी डिसॉर्डर से पीड़ित व्यक्ति की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है । इससे उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो जाती है। वह किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ऐसे लोगों की स्मरण-शक्ति कमज़ोर पड जाती है और इनका दांपत्य जीवन भी तनावग्रस्त रहता है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अगर स्त्रियों में एंग्जायटी डिसॉर्डर हो तो वे जल्द ही इससे बाहर निकल आती हैं, लेकिन पुरुषों में यह समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उनका अहं समस्या को आसानी से स्वीकार नहीं पाता। इसलिए वे उसका हल ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। अगर लंबे समय तक समस्या हो तो वह डिप्रेशन का रूप ले सकती है। ज्यादा गंभीर स्थिति होने पर व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

प्रमुख लक्षण

- शारीरिक दुर्बलता
- याद्दाश्त में कमी
- लगातार चिंतित रहना
- एकाग्रता में कमी आना, आंख के आगे तैरते हुए बिंदु दिखाई देना
- घबराहट, डर और बेचैनी
- नकारात्मक विचारों पर काबू न होना व डरावने सपने दिखना
- अनिद्रा
- शरीर के तापमान में असंतुलन, कभी हाथ-पैरों का ठंडा पड़ जाना तो कभी बुखार जैसा महसूस होना ।
- दिल की धड़कन तेज होना
- मांसपेशियों में तनाव होना
- पेट में दर्द

कैसे करें बचाव

- नियमित दिनचर्या अपनाएं क्योंकि नींद की कमी से मस्तिष्क पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता । अनिद्रा से एंग्जायटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है।
- शरीर की तरह मस्तिष्क को भी पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने भोजन में फलों और हरी सब्जियों को प्रमुखता से शामिल करना चाहिए ।
- नियमित एक्सरसाइज और योगाभ्यास करें। इस समस्या से बचने के लिए ध्यान भी फायदेमंद होता है। इससे सेरिब्रल कोरटेक्स को मजबूती मिलती है, मस्तिष्क का यही हिस्सा स्मरण-शक्ति, एकाग्रता और तर्क शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है।
- अगर जीवन में कभी कोई मुश्किल आए तब भी आत्मविश्वास बनाए रखें ।
- लोगों के साथ दोस्ती बढाएं और खुलकर अपनी भावनाएं शेयर करें
- अपनी क्षमताओं का आकलन करके व्यावहारिक लक्ष्य बनाएं। कार्यों की प्राथमिकता तय करें। एक साथ कई काम करने से बचें।
- अगर कभी किसी बात को लेकर एंग्जायटी हो तो उसका सामना करने की आदत डालें। उससे बचने की कोशिश कभी न करें, क्योंकि व्यक्ति ऐसी मनोदशा से जितना अधिक बचने की कोशिश करता है, समस्या उतनी ही तेजी से बढ़ती जाती है।
- ऐसी समस्याओं को छोटे-छोटे टुकडों में बांट कर हल करने की कोशिश करें। एक ही दिन में इनका समाधान संभव नहीं है। इसलिए धैर्य के साथ प्रयास करें ।
- नियमित रूप से एंग्जायटी डायरी मेंटेन करना भी फायदेमंद साबित होगा। रोजाना रात को सोने से पहले अपनी डायरी में विस्तृत रूप से लिखें कि आज दिन भर में आपको किस चिंता या भय ने सबसे ज्यादा परेशान किया और उसे दूर करने के लिए आपकी ओर से क्या कोशिश की गई।
- मन को तार्किक ढंग से समझाने की कोशिश करें कि यह आशंका निराधार है।
- एंग्जायटी दूर करने के लिए अपने मन से कोई दवा न लें ।
- कैफीन और एल्कोहॉल से दूर रहें, क्योंकि ऐसी चीजों के सेवन से एंग्जायटी बढती है ।
- इन प्रयासों के बाद भी अगर मनोदशा में कोई सुधार न आए तो किसी मनोवैज्ञानिक सलाहकार से संपर्क करना चाहिए ।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

RESTRUCTURING INDIAN ECONOMY - A PERSPECTIVE

India has been known for the unity among diversities and this is not only in the varied terrains, culture, religions and languages, but this reflects in different walks of life. A huge nation of 136 crore people blessed with abundant natural resources is gradually moving towards becoming 5th largest economy of the world, however there are challenges to overcome the decades long legacy of less accountability of service delivery system towards people. In general, the economy of any nation depends upon four major factors:

- level of conduciveness of the regulatory environment where individual can independently think and embark businesses.
- availability of natural resources
- capacity and capability of the country to exploit the resources judiciously.
- level of external trades especially export

Apart from these there are auxiliary concerns having direct impact on the border aspects. These include skilling environment, appreciation of the use of the people's time i.e. employability and social life style of the people.

Having significant impact of the ancient Indian philosophical and mythological thoughts, India possesses the capacity to survive even during economic crises and this capacity is lesser in other parts of the world. In fact, we have learnt to save and spend out of our savings, whereas the trend outside is to spend for material things out of loan which is easily available and keep on working for its recovery. It means if one loses employment, there arises problem of loan repayment. However, the new trend in India is also indicating the race towards the same and the majority of the service class people are working hard to repay loan instalments. Their survival becomes difficult if they are away from job even for 2-3 months. Services of banks have become far better than earlier times and thanks to the technology for bringing transparency and reducing time for various processes in banking. As there is always scope for improvement, certain areas still need to be looked into with open eyes, as outlined below:

1. Redefining System: Majority of our laws, procedures and processes being implemented were devised long back and some of them are even from British time. There is immediate need to review all such processes and procedures and come up with simple, easy to understand and easy to implement processes. Especially the time boundness for each and every process can be the key element of the game change.

2. Easy Banking: Notwithstanding the technological interventions in banking sector, one thing which can be proved as illegal and illogical is to put hundreds of signatures on the loan document written in English (somewhere in bilingual as well) in very small fonts in the language difficult to understand. When a person not understanding the clauses, is made agreed to and abide by simply putting signatures, should not become subject of interrogation in any court of law for such clauses which one never understood. The long documents with legal language don't have any meaning for the common man. And on contrary to it

even if one intends to read the documents, it may take one month to understand and that too when taught by some lawyer. Why should not there be a single page document clearly and in simple language mentioning the major terms and conditions of vital importance?

3. Self-Regulatory Banking: In the age of technology we need to review the level where one can take advantage of all banks facilities without visiting banks. Net-banking gives such privileges for online basic banking transactions, but availing loan from bank is a big headache. All manual procedures, collection and authentication of documents from various quarters is something which discourages budding entrepreneurs to change the business mindset and opt for job somewhere. Furthermore, there is no timeline for sanctioning proposal. The process is highly cumbersome and demotivating.

When costumers wish to avail money against their own property or assets, there should be one National Level Portal where all processes of availing loan and mortgaging assets against predefined market values can be exercised by the individuals without visiting bank and creating bundles of documents for putting hundreds of signatures. This can be done by integrating pre-defined parameters in the application with due authentication process.

4. Easy and Self-Managed licensing: Where there are needs of various NOCs and licenses, visiting different government authorities and encounter with inspector's policing attitude has to be vanished now. Portal should be constructed in such a way that one operates at

own for all such licenses and generate online testimony. The compliances and adherences can be processed through the technology and human interference has to be minimized.

5. Strong Quality Standards: the quality Standards need to be enforced very strongly with all punitive provisions and there should be no scope for deviation and shortcuts for escape. Again this role has also to be performed through the technologies otherwise the people will always be subject to suspect because of interference of power, favoritism and illegal wants.

6. Support to Agriculture: Agriculture contributes to around 18% of our GDP with engagement of about 50% of our work force; hence needs due attention. Farmers have been struggling with wild lives attacks, draught, floods and excessive chemicals apart from the marketing part.

If farmers start moving away from agriculture, there will be hue & cries across country and the present scenario seems leading us to such situation. There is need of holistic support to farming community right from soil test and treated seeds, bio-pesticides, manure, implements, technical know-how, solar fencing post-harvest support and marketing.

If attention is paid to the above points, the economy of our country can be expected to move faster through more engagement of people in different activities promoting thereby the social harmony.

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

ग्लोबल वार्मिंग की आहट...

जलने लगी है धरती...विनाश के स्पष्ट संकेत

एक लंबे समय से ग्लोबल वार्मिंग पर बहस, चर्चा, सेमिनार और भाषण प्रतियोगिताओं का दौर चलता रहा है। अधिकतर लोग तो इस शब्द को सुन-सुन कर ही बस इतना समझ पाये कि गर्मी बढ़ रही है और इस पर मंथन हो रहा है। लेकिन आज स्थिति इतनी भयावक हो चुकी है कि इस विनाशकारी स्थिति पर मंथन ही नहीं अमल करने की आवश्यकता है। बेमौसमी बारिशों का दौर, ग्लेशियरों का लगातार पिघलना, मौसम में बेतहाशा गर्मी और सर्दी का असर... ये सब कुछ भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हो सकते हैं। इस बार भी भारत की ही बात करें तो गर्मी ने कितनों के प्राण ले लिए साथ ही जीना भी दुभर कर दिया। यहां केवल राजस्थान के चुरु क्षेत्र की ही बात नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी सूरज ने ऐसी तपिश दी कि प्राण सूखने लगे। लेकिन इस बात से हम बेख़बर है कि हमारी करतूतें हमें और हमारी पीढ़ी का भविष्य जला देंगी। हमारा सारा ध्यान देश की आबादी बढ़ाने पर केन्द्रित है। आने वाले समय में शीघ्र ही हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले तमके को गले में टांग कर चलने वाले हैं। चीन हमसे अब पिछड़ जाऐगा। इतनी बड़ी आबादी का स्वच्छता और प्रदूषणमुक्त होने का सपना जंगलों और सड़कों पर कूड़े के ढेर पर चूर-चूर होता हुआ दिखाई देता है। हमने अपने वातावरण को दूषित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है।

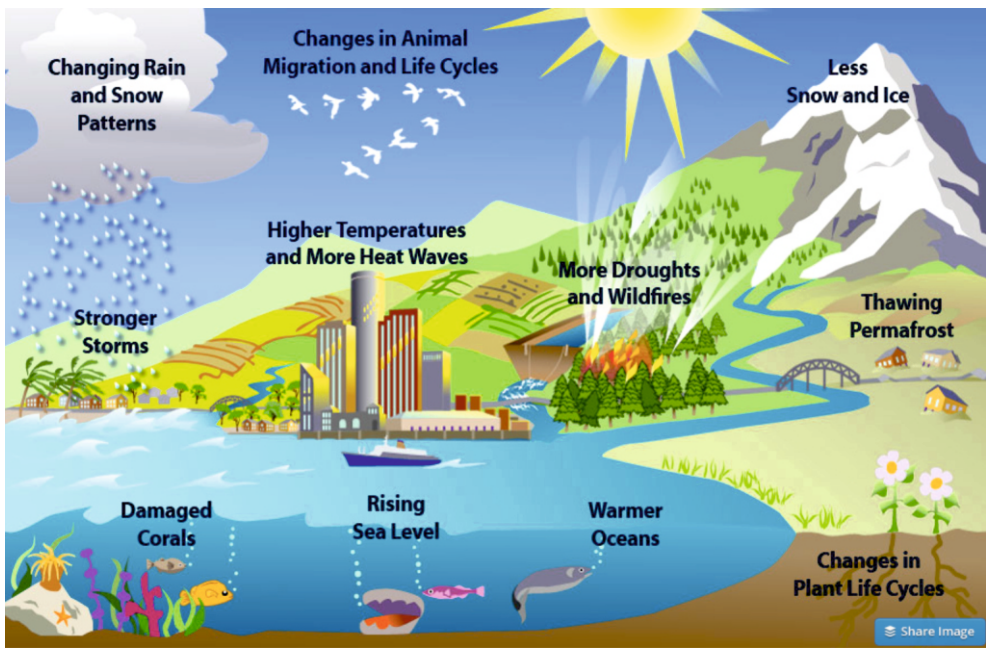

अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्यान देकर कहा कि भारत के लोगों को स्वच्छता की समझ ही नहीं है। इसमें सभी

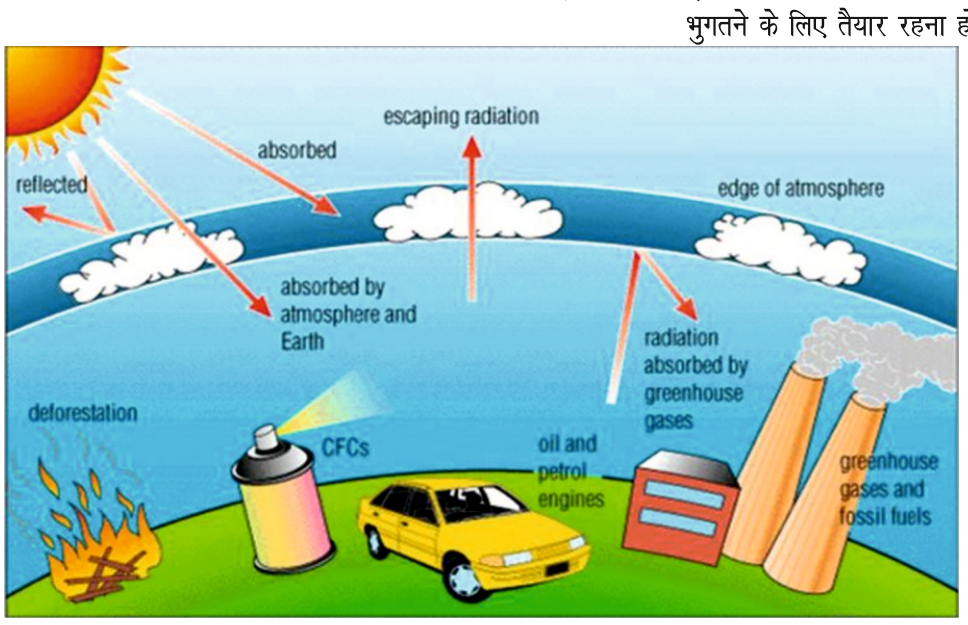

को बुरा लगने जैसा बहुत कुछ है लेकिन सच्चाई की कड़वाहट तो होती ही है। इसमें बुरा लगने जैसा कुछ है नहीं सिवाए इसके कि अमेरिका आज स्वयं सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जक देशों की श्रेणी में अग्रणी है। लेकिन भारत के संदर्भ में तो यह कहना ग़लत नहीं होगा कि यहां अभी एक टॉफी के कागज़ को कैसे व कहां फेंकना है, इस पर सेमिनार होते हैं। वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस प्रभाव, गैसों का प्रभाव तो एक सीमित आबादी को ही पता है।

विकास को हमने विनाश की कसौटी पर अधिक परखने का प्रयास किया है। आज देश में सड़कों और रेलवे का जाल बिछ गया है तथा यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। कंकरीट के जंगलों में बदलता भारत एक नई तस्वीर लिए सामने आ रहा है। किंतु यह विकास और तस्वीर असंख्य पेड़ों की निर्मम हत्या करके हरे-भरे जंगल को निर्जीव मैदान बना कर उकेरी गई है।

यहां प्रश्न ये है कि वैश्विक तापमपन में वृद्धि को रोके जाने की क्या व्यवस्था है ? क्या इंसान सजगता से इस बात को स्वीकार कर पा रहा है कि यदि शीघ्र ही न संभले तो पृथ्वी पर जीवन सरल नहीं रह जाऐगा। आरंभिक तौर पर यह कहना उचित होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैसें वो गैस है जो बाहर से मिल रही उष्मा या गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है। ग्रीन हाउस गैस का उपयोग वास्तव में उन स्थलों पर अधिक किया जाता है जहां पौधों को अत्यधिक ठंड के तापमान में बचाने के लिए ग्रीन हाउस गैस से संरक्षित किया जाता है। क्योंकि ये पौधे अत्यधिक ठंड के कारण ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए इन पौधों को कांच के घर में रख कर उसमें ग्रीन हाउस गैस को भर दिया जाता है जिससे यह गैस सूर्य से आने वाली गर्मी को सोख लेती है। यही प्रक्रिया हमारी पृथ्वी के साथ भी होती है।

ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस कार्बनडाईऑक्साइड होती है जो हम सांसों में बाहर उत्सर्जित करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि विगत कुछ वर्षों से हम विभिन्न माध्यमों से कार्बनडाईऑक्साइड का बेहद अधिक मात्रा में उत्सर्जन कर रहे है जिसका प्रभाव पर्यावरण के साथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह प्रभाव नितांत विपरीत है जो नुकसान ही कर रहा है। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के लिए 50 प्रतिशत जिम्मेवार कारक कार्बन उत्सर्जन ही है। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इतना ख़तरनाक होता है कि वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके इसका तापमान बढ़ा देता है। एक अनुमान के अनुसार 21वीं शताब्दी में यह तापमान 3 डिग्री से बढ़कर 8 डिग्री तक बढ़ जाऐगा। इससे सब कुछ ख़तरे के निशान में आ जाऐगा। ऐसा होने पर इसके घातक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। परिणाम बहुत ही विनाशक होंगे। दुनिया में बर्फ की फैली चादरों को पिघलने में अधिक समय नहीं लगेगा। इससे समुंद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाऐगा कि किनारों पर बसे शहरों का डूबने का सिलसिला शुरु हो जाएगा। जलमग्न होने में इन शहरों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह तबाही सुनामी या विभिशक युद्ध से भी भयंकर होगी।

अन्य कारण भी बेहद जिम्मेवार

ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के करणों के बाद भी मानवजनित कारण भयंकर स्थिति को पैदा करने में जिम्मेवार हैं।

- उद्योगों और कारखानों से निकलने वाली गैस के उत्सर्जन से पर्यावरण को प्रतिदिन व प्रतिक्षण भयंकर नुकसान हो रहा है। इसका व्यापक हल सरकार के पास नहीं है।
- फ्रीज़ और एयरकंडीशनर आदि के अत्यधिक उपयोग के कारण इस प्रकार की गैसों से ग्लोबल वार्मिंग का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका उपयोग हर घर में ही नहीं बल्कि हर दुकान, व्यवसायिक परिसरों आदि में भी दिन-रात हो रहा है। इसका विपरीत प्रभाव सामने है।
- हमारी जीवनशैली बेहद परिवर्तनशील है और इसका प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ रहा है। दिन-रात टेलिविजन, लाईट्स आदि ऑन मोड़ पर रहते हैं। हमें जिन कमरों में नहीं रहना होता है वहां भी अकारण ही हम विद्युत उपकरणों को ऑन रखते हैं। इस चकाचौंध भरी जीवनशैली का ग्लोबल वार्मिंग से सीधा संबन्ध है।
- प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव ख़तरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। धरती पर प्रदूषण के प्रति मानव जाति आज सजग तो है किंतु दस्तावेज़ी सजगता का औचित्य यहां न के बराबर है। प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान आने वाले दर्शक में 0.3 डिग्री तक बढ़ जाएगा जिसके बाद स्थिति ख़राब हो जाएगी।
- सी एफ सी गैसों का उत्सर्जन कम से कम किया जाना ज़रुरी है। इसके लिए फ्रीज़, एयरकंडीशनर, कूलिंग आदि का कम से कम उपयोग करना होगा।
- उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषित गैसों के निदान पर कुछ ठोस क़दम उठाने की आवश्यकता है।
- आज वाहनों की तादात इस हद तक बढ़ चुकी है कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण से भी ग्लोबल वार्मिंग में एक अहम कारक जुड़ रहा है। इसका निदान बहुत आवश्यक है।
- वृक्षों की कटाई इस हद तक की जा चुकी है तथा की जा रही है कि जंगल अब गुगल मैप में ही खिले-खिले दिखाई दे रहे हैं। वास्तविकता इससे उलट है। ग्लोबल वार्मिंग में यदि कोई कारक इसके संरक्षण में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है तो वो वृक्ष ही हैं। हमें इनके संरक्षण में जागरुक और सख़्त होने की आवश्यकता है। एक अनंत वृक्षारोपण एवं संरक्षण जन अभियान चले जिससे हम पृथ्वी को संरक्षित कर पाऐं।
- अक्षय उर्जा की ओर अब वैकल्पिक मार्ग खोजने का समय आ गया है। कोयले से बनने या चलने वाली प्रक्रिया को रोककर पवन उर्जा और सोलर उर्जा की ओर अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है। विद्युत को बनाने के लिए सोलर व पवन उर्जा का उपयोग हो। वाहनों के लिए भी सोलर पैनल ही ऊर्जा के माध्यम हो।

विभिन्न कारणों से एवं विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाऊस गैसों का विवरण निम्न है:

ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन	
पॉवर स्टेशन से	21.3 प्रतिशत
इंडस्ट्री से	16.8 प्रतिशत
यातायात व गाड़ियों से	14 प्रतिशत
खेती-किसानों के उत्पादों से	12.5 प्रतिशत
जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से	11.3 प्रतिशत
रिहायशी क्षेत्रों से	10.33 प्रतिशत
बॉयोमास जलने से	10 प्रतिशत
कचरा जलाने से	3.4 प्रतिशत

वर्तमान प्रयास नाकाफी

भारत सरकार के प्रयास हालांकि प्रशंसनीय कहे जाने चाहिए क्योंकि स्वच्छता अभियान को व्यापक पैमाने पर देश भर में यदि प्रभावी तरीके से परिणाम तक नहीं पहुंचा पाए तो कम से कम देश में जागरुकता तो आई ही है। किंतु हमें इस दिशा में बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। एक व्यापक जन जागरण अभियान जिसे सोशल मिडिया ही नहीं बल्कि स्कूलों में बच्चों की किताबों और पढ़ाई में शामिल करने की प्रबल आवश्यकता है। इसे केवल एक जिम्मेवारी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे नई पीढ़ी के संस्कारों में शामिल किये जाने की प्रक्रिया में लाना होगा। इस पृथ्वी पर जीवन होने जैसा पुनीत और कुछ हो ही नहीं सकता। यह पृथ्वी, पर्यावरण हमारे नाज़-नख़रे सहने के बाद भी

हमें जिस मातृत्व भाव और संरक्षण में पालती है, क्या हम उस धरा पर प्रदूषण और विनाश का उत्सर्जन कर उसकी कोख़ को कलंकित करने का घृणित अपराध नहीं कर रहे हैं ?

यदि पृथ्वी यों ही तपिश सहती रही तो एक दिन हमारी मनमानी के कारण ये बांध जब टूटेगा तो विनाश की ऐसी लीला होगी जिसमें इस धरा पर मानव जाति को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा विकास जो मानवता के अहित में विनाश को लेकर आए.... उससे परहेज़ आवश्यक है। हमें बदलना होगा, अपनी करतूतों को भी और अपने आचरण को भी। प्रकृति के संरक्षण में ही मानव संरक्षण समाहित है। ऐसा न हो कि ग्लोबल वार्मिंग पर निबंध लिखते-लिखते बच्चे इसी तपिश में झुलस जाऐं..... इसलिए यह कहना ग़लत न होगा कि पृथ्वी को बचाने पर ही हमारे अस्तित्व की साख बच पाऐगी।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

नॉन रिसाइक्लिबल पॉलिथीन वापिस खरीदने के लिए शुरु की जाएगी योजना : मुख्यमंत्री

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (एचएमसीओएसटी), हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हिमाचल प्रदेश पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 2018–19 के वितरण समारोह की अध्यक्षता की।

जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें शहर के 30 स्कूलों के लगभग 600 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने 'पर्यावरण उत्कृष्टता पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन' पुस्तक के अलावा अन्य जागरूकता प्रकाशन सामग्री का भी विमोचन किया। उन्होंने राज्य में पर्यावरण संरक्षण और सत्त विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। उन्होंने विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह के साथ-साथ नगद पुरस्कार प्रदान किए जिसमें प्रथम को 50,000 रुपये तथा द्वितीय को 25,000 रुपये शामिल है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि राज्य सरकार निर्धारित मूल्य पर नहन-रिसाइक्लिबल पॉलीथीन को वापिस खरीदेगी। इसके अलावा, उन्होंने पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्मित किए गए नए बैग का भी शुभारम्भ किया।

मानकों पर खरा नहीं उतर रही हिमाचल में बनी दवाएं, पांच माह में 60 के सैंपल फेल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

फार्मा हब के रूप में उभरे हिमाचल के उद्योगों में बनी दवाएं मानकों पर खरा नहीं उतर रही हैं। पांच माह में 60 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। जनवरी माह में देशभर की फेल हुई 45 दवाओं में हिमाचल की 14 दवा, फरवरी में देशभर की 37 दवाओं में 13, मार्च में देशभर की 50 में से 19, अप्रैल में 29 में से 6 और मई माह में 33 में से 8 दवाएं हिमाचल के उद्योगों की फेल हो चुकी हैं। बीते वर्ष देशभर में फेल हुई 350 दवाओं में से हिमाचल की 100 से अधिक दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं।

इस वर्ष के पांच माह में 60 दवाएं गुणवत्ता में खरी नहीं उतरी हैं। 45 फीसदी दवा निर्माण का तमगा हासिल करने वाले प्रदेश के लिए दवाओं के सैंपल फेल होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश भर में करीब 750 फार्मा उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से कई उद्योगों में निर्मित दवाओं पर सवाल उठते ही रहे हैं और सीडीएससीओ के हर माह के ड्रग अलर्ट के बाद विभाग हरकत में आता है और सैंपल फेल होने वाली दवाओं का बैच मार्केट से उठा लिए जाते हैं।

पुलिस ने किया अफीम की अवैध खेती का पर्दाफाश, उगाए जा रहे थे 15 हजार पौधे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पुलिस ने अफीम की अवैध खेती का पर्दाफाश किया है । मिली जानकारी के मुताबिक पधर पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट मंडी की सयुंक्त टीम ने चौहार घाटी में विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर भारी मात्रा में अफीम के पौधे बरामद किए। इस संबंध में अफीम की अवैध खेती करने वालों के खिलाफ चार मामले दर्ज किए गए हैं।

करीब 15 हजार अफीम के पौधे पाए गए हैं। पुलिस ने इन्हें नष्ट करने का अभियान छेड़ा है। डीएसपी पधर मदनकांत ने बताया कि 15 हजार अफीम के पौधे अवैध तरीके से उगाए जा रहे थे। पुलिस इन पौधों को नष्ट कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है।

आंगनबाड़ियों को जनसंख्या सही करने के दिए आदेश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार ने हिमाचल की आंगनबाड़ियों में फिर घोस्ट पॉपुलेशन हटाने के आदेश दिए हैं। घोस्ट पॉपुलेशन वे लाभार्थी हैं, जो असल में कागजों में ही हैं, धरातल पर नहीं हैं। केंद्र सरकार ने वास्तविक लाभार्थियों को ही बजट जारी करने को कहा है। यह लाभ देने के लिए आंगनबाड़ियों में आधार सत्यापन को भी जरूरी बताया गया है, जिससे गड़बड़ी की संभावना न्यूनतम हो जाए। साथ ही केंद्र सरकार ने हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए आईसीडीएस के तहत संयुक्त रूप से ग्रांट भी जारी की है। सप्लीमेंट न्यूट्रीशंस प्रोग्राम के तहत तीनों राज्यों को सामान्य कंपोनेंट की दूसरी किस्त के रूप में 16 करोड़ 3 लाख 51 हजार जारी किए गए हैं। हिमाचल को 479.62, जम्मू-कश्मीर को 292.67 और उत्तराखंड को 831.22 लाख जारी हुए हैं।

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

अनुसूचित जाति कंपोनेंट में इसी योजना के तहत 4 करोड़ 27 लाख 61000 रुपये दिए हैं। हिमाचल को 127.9 लाख, जम्मू-कश्मीर को 78.05 और उत्तराखंड को 221.66 करोड़ मिले हैं। अनुसूचित जाति कंपोनेंट में 1 करोड़ 6 लाख 89 हजार रुपये जारी हुए हैं। हिमाचल को 31.97 लाख, जम्मू-कश्मीर को 19.51 लाख और उत्तराखंड को 55.41 करोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अवर सचिव बचन सिंह की ओर से इस बारे में हिमाचल और दोनों पड़ोसी राज्यों की सरकारों के वित्त, स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिवों को मंजूरी पत्र भेजे गए हैं । इसमें साफ किया गया है कि यह योजना पूरी तरह से डीबीटी स्कीम है, इसलिए हर लाभार्थी का आधार नंबर से जोड़ना होगा।

मुख्यमंत्री ने जीआईए के तहत हिमाचली काला जीरा और चुल्ली तेल पंजीकृत होने पर प्रसन्नता व्यक्त की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सामान अधिनियम, 1999 के भौगोलिक संकेतक (जीआई) के तहत हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुल्ली तेल के पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास राज्य के पारंपरिक उत्पादों के संरक्षण में काफी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह बाजार की संभावनाओं को और बढ़ाएगा, जिसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की खेती में शामिल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण के लिए अधिसूचना संख्या-एसटीई-एफ (1) -6,2004 दिनांक 10 सितंबर, 2004 के तहत एक नीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र (एचपीपीआईसी) हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद को हिमाचल प्रदेश के संभावित भौगोलिक संकेतक (जीआई) की पहचान करने और जीआई अधिनियम के तहत इनका पंजीकरण करवाने के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया है ताकि प्रदेश के उत्पादकों/कारीगरों के हितों की रक्षा की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआई अधिनियम के तहत इन उत्पादों का पंजीकरण होने से अनाधिकृत उत्पादन पर रोक के साथ-साथ हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुल्ली तेल के नाम का दुरूपयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जीआई अधिनियम के तहत इन उत्पादों के मूल क्षेत्र के अलावा अन्य उत्पादकों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनाधिकृत उपयोग व उल्लंघन के परिणामस्वरूप कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।

हिमाचल उच्च न्यायालय को मिले दो नए न्यायाधीश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अधिवक्ता अनूप चिटकारा और अधिवक्ता ज्योत्सना रेवाल दुआ ने बृहस्पतिवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के क्रमशः न्यायधीश और अतिरिक्त न्यायधीश के तौर पर शपथ ली। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी ने उच्च न्यायालय में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने 1990 में उच्च न्यायलय में वकालत की । 2000 से वह अपराध संबंधी कानून में वकालत कर रहे हैं । वह अभी तक 500 से अधिक मामले लड़ चुके हैं। वहीं न्यायाधीश दुआ ने दिसम्बर 1991 में बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश में दाखिला लिया और तभी से वह वकालत कर रही हैं।

हिमाचल प्रदेश में जून, जुलाई में मछली पकड़ने पर रोक रहेगी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के सभी जलाशयों में जून और जुलाई में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा । राज्य के एक मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी ।

हिमाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि हर साल दो महीने के लिये प्रतिबंध लगाना नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान मछली की अधिकतर प्रजातियां प्रजनन प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां जन्म लेती हैं। उन्होंने कहा कि मछलियों की बिक्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा । मत्स्य मंत्री ने कहा कि राज्य के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को प्रतिबंध के दौरान तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे।

पॉलिथीन को लेकर हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सीएम जयराम ने दी जानकारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नॉन रिसाइक्लेबल पॉलिथीन को लेकर हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार निर्धारित मूल्य पर नहन रिसाइक्लेबल पहलिथीन खरीदेगी। यह पहलिथीन शहरी निकायों और अन्य कूड़ा एकत्र करने वाली संस्थाओं से लिया जाएगा। इसे सीमेंट फैक्टरी या सड़क जैसे निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा ।

विश्व पर्यावरण दिवस पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शिक्षा विभाग के संयुक्त रूप से आयोजित पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में सीएम ने पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की

मुख्यमंत्री ने दिया नीदरलैंड को राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश करने का न्योता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर एवं उनके प्रतिनिधिमंडल ने नीदरलैंड के एमस्टरडैम में कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता मंत्रालय के महासचिव जेन-कीस गोएट से कृषि, बागवानी एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने महासचिव को हिमाचल में फलोत्पादन के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान की गई व्यापक क्षमताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल को भारत का 'फल राज्य' कहा जाता है तथा यहां जलवायु विविधता होने के कारण विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि यहां फल एवं खाद्यान प्रसंस्करण में व्यापक निवेश की संभावनाएं उपलब्ध हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि नीदरलैंड ने जल प्रबंधन और कृषि तथा बागवानी में कम भूमि का उपयोग करके उन्नत पद्धतियों को अपनाया है, जो हिमाचल जैसे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं।

उन्होंने दिल्ली में 3–4 नवंबर को 'वर्ल्ड फूड एक्सपो' के तुरंत बाद नवंबर 2019 में धर्मशाला में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में नीदरलैंड के महासचिव और उनके मंत्रालय को आमंत्रित किया।

कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता मंत्रालय के महासचिव जेन-कीस गोएट ने कहा कि नीदरलैंड ने तीन मुख्य हितधारकों अर्थात सरकार, अनुसंधान केन्द्रों और कृषि व्यवसायों के बीच सहयोग का सुनहरा त्रिकोण बनाया है। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री के निमंत्रण को भी स्वीकार किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 1160 करोड़ रुपये की मांग की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने उनके तीन दिवसीय नई दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय स्वस्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात की और प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत बनाने और चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए 1160 करोड़ रुपये प्रदान करने का आग्रह किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में सात अन्य ट्रॉमा केन्द्र स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि प्रत्येक केन्द्र के लिए मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण सड़क दुर्घटना से राज्य में मृत्यु दर अधिक है। उन्होंने कहा कि रामपुर ट्रॉमा सेंटर के लिए भी 4 करोड़ रुपये की भी आवश्यकता है।

उन्होंने तीन जिला अस्पताल जो कि मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किए गए थे तथा मौजूदा आई.जी.एम.जी शिमला को मजबूत बनाने के लिए 800 करोड़ रुपये की मांग की और कहा कि राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान को भी 295 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए मुफ्त डायगनोस्टिक सेवाएं सुविधा प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट की भी मांग की।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश भारत की 70 प्रतिशत जेनेरिक दवाईयों का उत्पादन कर रहा है और बद्दी में ड्रग जाँच लेब स्थापित करने के लिए 15 करोड़ रुपये की पहले से ही स्वीकृति मिल चुकी है हालांकि लेब स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 15 करोड़ रुपये के बजट की आवश्यकता है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मालदीव के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मालदीव ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा की राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने के अपने फैसले की घोषणा की है। अपने कार्यकाल की दूसरी पारी की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेश दौरे पर मालदीव के लिए रवाना हो गए हैं। यह विदेशी प्रतिनिधियों को दिया जाने वाला मालदीव का सबसे बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनके नेतृत्व में भारत और मालदीव के बीच दोस्ती को मजबूती मिली और दोनों देशों के बीच दशकों पुराने रिश्तों पर उत्तरोत्तर कार्य हो रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले सऊदी अरब और रूस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है।

मेघालय में एनपीपी ने रचा इतिहास, पूर्वोत्तर की पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) को चुनाव आयोग से राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पूर्वोत्तर के किसी स्थानीय पार्टी को यह दर्जा मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा की अध्यक्षता वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी इसके लिए सभी जरूरी अहर्ताएं पूरी कर ली थी। एनपीपी केंद्र में सत्तारुढ़ एनडीए का सहयोगी दल है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, अगर कोई पार्टी चार राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता रखता है तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता रखने के लिए सभी आवश्यक शर्तें भी पूरी करती है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद देश में किसी भी अन्य राजनीतिक दल या प्रत्याशी को एनपीपी का 'किताब' वाला चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान में कुल सात राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था।

आरबीआई ने रेपो रेट में की कटौती, होम लोन हो सकता है सस्ता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आरबीआई ने 06 जून 2019 को अपनी क्रेडिट पॉलिसी जारी की। इसमें आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की घोषणा की। आरबीआई ने इस तरह लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है। अब रेपो रेट 6 फीसदी से घटकर 5.75 फीसदी हो गई है।यह रेपो रेट पिछले 9 साल में सबसे कम है। रेपो रेट में कमी से सभी तरह के लोन सस्ते होंगे। शक्तिकांत दास के आरबीआई के गवर्नर बनने के बाद यह लगातार तीसरी कटौती है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल की पॉलिसी में भी आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की गई थी। आरबीआई द्वारा अब तक तीन पॉलिसी में 0.75 फीसदी की कटौती की जा चुकी है।

विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून को विश्व भर में मनाया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

05 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है। हरेक विश्व पर्यावरण दिवस पर पृथक आयोजक देश का चयन होता है जहां आधिकारिक समारोह का आयोजन किया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 1974 को मनाया गया था। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1972 में मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके दो साल बाद, 05 जून 1974 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। साल 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग-अलग देशों को चुना जाता है।

द्वितीय विश्व युद्ध से एएन-32 तक वैलीज ऑफ नो रिटर्न में दफन हो चुके हैं सैकड़ों विमान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय वायुसेना के लापता हुए विमान का मलबा अरुणाचल प्रदेश के लीपा में मिला। तीन जून का लापता हुए इस विमान ने असम के जोरहाट बेस से 13 जवानों के साथ उड़ान भरी थी। हालांकि, इससे पहले भी दो एएन-32 विमान लापता हो चुके हैं और उनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। लेकिन, इसके साथ ही एक रहस्य और है जो उस जगह से जुड़ा है जहां इस विमान का मलबा मिला। दरअसल, अरुणाचल प्रदेश में जिस स्थान पर इस विमान का मलबा मिला उन घाटियों के आस-पास पहले भी विमानों के मलबे मिलते रहे हैं। इनमें से कई विमान ऐसे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय लापता हो गए थे। दरअसल, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 540 विमान लापता या दुर्घटना के शिकार हो गए थे। शायद यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश की इन घाटियों को वैलीज अहफ ने रिटर्न कहा जाता है। बचाव टीम को दुर्घटनास्थल तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि ईस्ट अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां बेहद रहस्यमयी मानी जाती हैं और यहां पहले भी कई बार ऐसे विमानों का मलबा मिला है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लापता हो गए थे। जिस जगह पर विमान का मलबा मिला है, वह करीब 12 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। साल 2018 के जनवरी महीने में अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के जंगलों में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के विमान के अवशेष मिले थे। स्थानीय युवाओं के एक दल ने विश्व युद्ध के दौरान वहां विमान गिरने की कहानियां सुनते-सुनते उसे ढूंढ निकालने का फैसला किया। इन्होंने 10 जनवरी को विमान के अवशेष ढूंढ निकाले। वहीं, इसी साल पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के रोइंग जिले के तीन स्थानीय पर्वतारोही सुरिंधी पहाड़ी पर जड़ी-बूटियां खोजने गए थे। हालांकि, उन्हें जड़ी-बूटी तो नहीं मिली, लेकिन मिल गया 75 साल पुराना एक हवाई जहाज। यह अमेरिकी वायुसेना का विमान था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ लड़ाई में चीन की मदद के लिए असम के दिनजान एयरफील्ड से उड़ान भरी थी। विमान के मलबे में बड़ी संख्या में गोलियां, एक चम्मच, कैमरे के लेंस और और ऊनी दस्ताना मिला था।

केरल में खतरनाक निपाह वायरस की फिर पुष्टि, जानें इसके लक्षण और बचाव

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में केरल में एक बार फिर खतरनाक निपाह वायरस का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने राज्य में निपाह वायरस के पहले मामले की पुष्टि की है। दरअसल, केरल के 23 साल के एक छात्र को निपाह वायरस से संक्रमित होने के शक में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निपाह वायरस की पुष्टि पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) की रिपोर्ट में हुई है। केरल में साल 2018 में ही निपाह वायरस से कोझिकोड और मलप्पुरम जिले में करीब 16 जानें गई थीं। दरअसल निपाह वायरस स्वाभाविक रूप से कशेरुकी जानवरों से मनुष्यों तक फैलती है। यह रोग साल 2001 में और फिर साल 2007 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी सामने आया था।

आंध्र प्रदेश के सीएम ने राज्य की आशाकर्मियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

03 जून 2019 को आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की आशाकर्मियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा दिया है। इस समय आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाकर्मियों को 3000 रुपए का मासिक मानदेय मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने यह वेतन 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद 30 मई 2019 को जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने 46 साल के जगनमोहन रेड्डी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाईएसआर कांग्रेस ने राज्य विधानसभा की 175 में से 151 सीटों पर जीत दर्ज की।

चीन ने पहली बार समुद्री जहाज से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

05 जून 2019 को चीन ने पहली बार समुद्री जहाज से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया। चीन पिछले कुछ सालों से लगातार अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को प्राथमिकता दे रहा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शानडोंग प्रांत में पीत सागर में एक चलित प्लेटफार्म से एक 'ए लांग मार्च-11 सॉलिड प्रोपेलेंट कैरियर रॉकेट' ने उड़ान भरी। इसी कड़ी में बीजिंग 2020 तक मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की योजना पर भी काम कर रहा है। चीन ने समुद्र स्थित प्लेटफार्म से पहली बार अंतरिक्ष में रॉकेट लांच किया है। यह लांग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज का 306वां अभियान है। चीन समुद्र से रॉकेट लॉन्च करने वाला तीसरा देश बन गया है। यह उपलब्धि उससे पहले अमेरिका और रूस ने हासिल की थी।

कठुआ रेप मामला: कोर्ट ने छह अभियुक्तों को सजा दी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कठुआ में जनवरी 2018 में आठ साल की एक बच्ची के साथ गैंग रेप, प्रताड़ना और हत्या मामले में छह दोषियों में से तीन को अदालत ने उम्र कैद की सजा दी है। पठानकोट की फास्ट ट्रैक अदालत ने सांजी राम को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो पुलिस वालों को भी पाँच-पाँच साल की कैद की सजा सुनाई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के आरोप पत्र के अनुसार, 10 जनवरी 2018 को अगवा की गई आठ साल की मासूम बच्ची को कठुआ जिले में एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया और उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसे जान से मारने से पहले उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया। करीब एक हफ्ते बाद 17 जनवरी 2018 को जंगल में उस बच्ची की लाश मिली थी।

युवराज सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया सन्यास

द रीव टाइम्स ब्यूरो

युवराज सिंह ने 18 साल के लंबे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। युवराज सिंह ने मुंबई में एक प्रेस कांफ्रेस के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि अब वो कैंसर पीड़ितों की मदद करेंगे। युवराज सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहते समय भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि विश्वकप जीतना सपना था।

अमेरिका ने भारत को सशस्त्र ड्रोन बेचने की मंजूरी दी जानिए इसकी खासियत

इस ड्रोन के आने से भारत की सामरिक शक्ति बढ़ेगी। इससे सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत-प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। अमरीका से यह अनुमति भारत की सीमाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी करना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के हित में सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाना है। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत भी भारत के लिए चिंता का विषय रही है। इसके साथ ही भारत एशिया में संतुलन शक्ति स्थापित करने में भी अमेरिका के लिए मददगार साबित हो सकेगा। ट्रंप सरकार अपनी सबसे बेहतर सैन्य तकनीक को भारत को ऑफर करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

अजीत डोभाल पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कैबिनेट रैंक दिया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को केंद्र सरकार द्वारा पुनः राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अजीत डोभाल को मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की वायुसेना की रणनीति को मूल रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमलीजामा पहनाया था।

बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार होंगे 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वीरेंद्र कुमार भारत की 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने साल 1996-2009 के बीच मध्य प्रदेश के सागर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे अभी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इस बार भी टीकमगढ़ की सीट से जीतकर आए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली पहली सरकार में वह अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मिनिस्ट्री में राज्यमंत्री थे।

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गिरीश कर्नाड का निधन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

10 जून 2019 को बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता गिरीश कर्नाड का निधन हो गया। वे 81 साल के थे। गिरीश कर्नाड पिछले कई दिनों से बीमार थे। गिरीश कर्नाड ने सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, में भी काम किया था। वे दस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं। उन्हें दक्षिण भारतीय रंगमंच और फिल्मों का पितामह माना जाता था। गिरीश कर्नाड को साल 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साल 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, साल 1974 में पद्म श्री, साल 1992 में पद्म भूषण, साल 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साल 1992 में कन्नड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार, साल 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और साल 1998 में उन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

चीन की देशवासियों से अपील, ना जाएं अमेरिका, वहां नहीं सब ठीक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चीन ने देशवासियों से अमेरिका की यात्रा करने को लेकर चेतावनी जारी की है। चीन का मानना है कि उनके और अमेरिका के बीच कारोबारी तनाव काफी बढ़ गया है, इसको लेकर उसके नागरिकों वहां पर उत्पीड़न और सार्वजनिक सुरक्षा का शिकार हो सकते है। बता दें कि यह चेतावनी चीन के एक दिन पहले किए अपने छात्रों से अमेरिका में पढ़ाई ना करने के आगाह के बाद आई।

चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने अमेरिका में यात्रा करने वाले चीनी पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया। उनका मानना है कि इससे अमेरिकी यात्रा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होगा। मंत्रालय ने हाल ही में अमेरिका में हुई गोलीबारी, डकैती और चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए चीनी पर्यटकों को अमेरिका की यात्रा के जोखिमों का पूरी तरह से आकलन करने की चेतावनी दी है।

गहरे अंधेरे समुद्र में रहती है ये मछली, पारदर्शी होते हैं ड्रैगन फिश के दांत

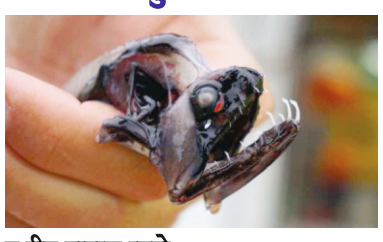

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गहरे समुद्र में पाई जाने वाली ड्रैगनफिश के दांतों के पारदर्शी होने का कारण वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। वैज्ञानिकों की मानें तो इन्हीं दांतों की मदद से ड्रैगनफिश एक छद्मआवरण बनाकर अन्य छोटे जलीय जीवों को अपना शिकार बनाती है। ड्रैगनफिश के दांतों की इनेमल जैसी परत में हाइड्रोक्सीपेटाइट नैनोक्रिस्टल्स होते हैं जो इस तरह से संरचित होते हैं जो प्रकाश को दांतों की सतह पर बिखरने या प्रतिबिंबित करने से रोकता है। जिसके कारण आसानी से इनके दांत पहचान में नहीं आते।

मैटर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, उनके असामान्य और अव्यवस्थित दांत क्रिस्टलीय नैनोस्ट्रक्चर के मिश्रण से बने हैं, जो पारदर्शी सिरेमिक बनाने के लिए शोधकर्ताओं को (बायो इंस्पिरेशन) प्रेरणा दे सकते हैं। सेरेमिक एक अकार्बनिक व अधात्विक ठोस है, जिसका निर्माण धात्विक व अधात्विक पदार्थों से होता है। इसकी सतह को उच्च तापमान पर गर्म करके कठोर, उच्च प्रतिरोधकता युक्त बनाया जाता है।

52 हजार माइक्रोप्लास्टिक कण निगल रहे हम ब्रांडेड पानी बोतल में भी मौजूद है ये प्रदूषण

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुके जल और वायु प्रदूषण से बचने के लिए विश्वभर में नए-नए उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि, प्लास्टिक प्रदूषण एक ऐसी समस्या बनकर उभर रही है, जिससे निपटना अब भी दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। साल दर साल प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पीने के पानी, भोजन और हवा को दूषित करता जा रहा है। हाल में हुए एक शोध के अनुसार एक वर्ष में 52 हजार से ज्यादा प्लास्टिक के माइक्रो कण खाने-पानी और सांस के जरिए इंसान के अंदर जा रहे हैं। इंसानी शरीर को अंदर से प्रदूषित कर रहे प्लास्टिक के माइक्रों कणों की वजह, हमारे खाने, पानी, कपड़ों और रोजमर्रा की अन्य चीजों में तेजी से बढ़ रहा प्लास्टिक का प्रयोग है। प्लास्टिक का ये प्रदूषण इसलिए बेहद खतरनाक हैं क्योंकि इसके माइक्रो कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं है।

भारतवंशी छात्रा ने दुबई में जीता अमीरात रिसाइकिलिंग अवार्ड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई शहर में रहने वाली आठ वर्षीय भारतवंशी छात्रा निया टोनी ने देश को साफ-सुथरा रखने के अभियान के तहत 15 हजार किलोग्राम रद्दी कागज इकट्ठा किया है। निया के इस अभूतपूर्व प्रयास के लिए एक समारोह में उसे अमीरात रिसाइकिलिंग अवार्ड से नवाजा गया। अमीरात एनवायर्नमेंटल ग्रुप के तत्वावधान में यूएई में लंबे समय से चल रहे वेस्ट रिसाइकिलिंग अभियान के तहत निया ने इतनी बड़ी मात्रा में रद्दी पेपर जमा किया। उन्होंने अपने आस-पड़ोस में खुद घूमकर रद्दी इकट्ठा की और इलाके को साफ-सुथरा रखने में योगदान दिया।

आस-पड़ोस को साफ-सुथरा रखने वालों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस समारोह में रद्दी पेपर के अलावा प्लास्टिक, गिलास, कैन और मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा करने वालों को भी सम्मानित किया गया। यूएई में सफाई को लेकर चले इस अभियान के तहत 73 हजार टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कम किया गया।

डोनाल्ड ट्रंप बोले- भारत में ना शुद्ध हवा, ना साफ पानी, प्रदूषण की भी समझ नहीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त और कहा जाए तो भारत के सबसे भरोसेमंद साथी अमेरिका ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत में ना साफ हवा है और ना ही पीने लायक साफ पानी। यहां तक कि भारत को तो प्रदूषण तक की समझ नहीं है। ब्रिटेन के एक टीवी चैनल आईटीवी को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा- "भारत के साथ कई देशों में हवा तक साफ नहीं है, ना वहां पीने का साफ पानी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा- "अगर आप कुछ शहरों में जाएं.. मैं उन शहरों का नाम नहीं लूंगा, हालांकि मैं ले सकता हूं। इन शहरों में आप सांस तक नहीं ले पाएंगे।

वैज्ञानिकों ने माना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बीते 50 सालों में बढ़े अत्यधिक बारिश के मामले

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा बारिश कई बार अपने साथ बाढ़ जैसी तबाही और जलजनित बीमारियां लेकर आती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन (ग्लोबल वार्मिंग) के कारण बीते 50 साल में दुनियाभर में अतिवृष्टि के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। वाटर रिसोर्सेज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 1964 से लेकर 2013 तक अत्यधिक बारिश की सर्वाधिक घटनाएं हुई और यह वही समय था जब ग्लोबल वार्मिंग भी तेज हो गई थी। अध्ययन के मुताबिक, अत्यधिक वर्षा की घटनाएं कनाडा के कुछ हिस्सों, यूरोप, अमेरिका के मध्य - पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी रूस और चीन के कुछ हिस्सों में बढ़ी हैं। कनाडा में सास्काचेवान यूनिवर्सिटी में हाइड्रो - क्लाइमेटोलॉजिस्ट साइमन पापालेइसीउ ने कहा 'इस अध्ययन के लिए वैश्विक स्तर पर सैकड़ों बारिश के रिकॉर्ड खंगाले गए, जिसमें हमने पाया कि बीते 50 साल के दौरान जब ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आनी शुरू हुई तो अतिवृष्टि के मामले भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी देखी गई। यह बदलती प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति आगाह करती है।

नासा की इस तकनीक से भविष्य में हजारों छोटे मानवरहित एयरक्राफ्ट एक ही समय में उड़ाए जा सकेंगे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नासा ने शहरों में ड्रोन के लिए नेशनल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के अपने चार साल के प्रयासों का अंतिम चरण शुरू किया है। इसके तहत नासा पहली बार शहरों में ड्रोन का परीक्षण कर रहा है। शहरों की बड़ी बिल्डिंगों और व्यस्त सड़कों में ड्रोन चलाने के लिए एक कुशल और प्रभावी तंत्र की जरूरत है। साथ ही यह भविष्य में नए व्यवसाय का भी निर्माण करेगा। सिमुलेशन टेस्टिंग के दौरान नासा ने इस सप्ताह अमेरिका के नेवादा राज्य के एक शहर रेनो के ऊपर एक साथ एक ही समय में कई ड्रोन उड़ाए। नासा की इस उभरती हुई तकनीक के इस्तेमाल से भविष्य में हजारों छोटे मानवरहित एयरक्राफ्ट एक ही समय में उड़ाए जा सकेंगे। जिनके माध्यम से खाद्य सामाग्री, दवाओं आदि की डिलीवरी आसानी से की जा सकेगी। कैलिफोर्निया में नासा के रिसर्च सेंटर में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विभाग के निदेशक डेविड कोर्सेमर ने बताया कि एक साथ कई ड्रोन को एक समय पर उड़ाना इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। नासा ने इस तरह के परीक्षण दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी किए हैं।

न्यूजीलैंड ने विश्व का पहला 'वेलबीइंग बजट' पेश किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

न्यूजीलैंड सरकार द्वारा 30 मई 2019 को विश्व में पहली बार 'वेलबीइंग बजट' पेश किया गया। न्यूजीलैंड सरकार के वित्तमंत्री ग्रांट ने इस 'वेलबीइंग बजट' में एक बड़ा हिस्सा बाल गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा रोकने के लिए सुरक्षित रखा है। न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए संसद में कहा कि न्यूजीलैंड में रह रहे बहुतायत लोगों को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाया है जिसके चलते इस प्रकार का बजट लाया गया है।

न्यूजीलैंड सरकार का कहना है कि 'वेलबीइंग बजट' बजट असमानता की चुनौती से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बना गया है जिसने बजट में आर्थिक विकास दर को प्राथमिकता न देते हुए लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी है, इसलिए इसे वेलबीइंग बजट कहा गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अनुमान लगाया है कि न्यूजीलैंड के इस बजट के बाद देश अर्थव्यवस्था की विकास दर 2019 में 2.5 प्रतिशत और 2020 में 2.9 प्रतिशत रह सकती है।

इजराइल ने होम्स प्रांत में एयरबेस पर दागे रॉकेट, सीरिया ने किया नाकाम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सीरिया ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने अपने रॉकेटों से होम्स प्रांत में एक एयरबेस को निशाना बनाया है। सरकारी समाचार एजेंसी सना ने सैन्य सूत्र के हवाले से बताया कि 24 घंटे के अंदर यह दूसरा रॉकेट हमला था। एजेंसी के मुताबिक, सीरिया की हवाई रक्षा प्रणाली ने इजराइल के एक हमले को नाकाम कर दिया और टी-4 एयरबेस को निशाना बनाकर दागे गए दो रॉकेटों को मार गिराया। कुछ रॉकेट जमीन पर भी गिरे जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। इसके अलावा हथियार डिपो को नुकसान पहुंचा है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि इस हमले में एक सैनिक समेत कुल पांच लोगों की मौत हुई है।

हमले के वक्त एयरबेस पर सीरियाई सेना के अलावा, ईरानी लड़ाके और हिज्बुल्ला के अर्धसैनिक बल भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि इजराइल ने ईरान और हिज्बुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाने के बहाने कथित तौर पर सीरिया पर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि वह ईरान को सीरिया में सैन्य रूप से घुसने से रोकने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीरिया में जारी लड़ाई में अब तक 3,70,000 लोग मारे गए हैं। पिछले आठ साल से जारी लड़ाई के बावजूद सीरिया में ईरान समर्थित राष्ट्रपति बशर अल असद अपने पद पर बरकरार हैं।

बस दुर्घटना : 12 भारतीय नागरिकों की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

दुबई में बीत दिनों एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 17 लोगों की मौत हो गई जिसमें से 12 भारतीय हैं। बस ओमान से दुबई जा रही थी और रास्ते में लगे साइनबोर्ड के साथ टक्कर में यह हादसा हुआ। बस में 31 यात्री थे। ये जानकारी दुबई पुलिस ने दी है। बता दें कि मारे गए लोगों में से 12 भारतीय नागरिक हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुबई में हुए इस बस हादसे में 12 भारतीयों की मौत की पुष्टि की है।

भारत का आम चुनाव सबसे ऐतिहासिक और समावेशी चुनावः संयुक्त राष्ट्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के लोकसभा चुनावों को सबसे ऐतिहासिक और समावेशी चुनाव बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सचिव शकुंतला डोई गैमलिन ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कहा, भारत में हुए लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक और समावेशी चुनाव रहे। ऐसा इसलिए कि वहां चुनावों में हर व्यक्ति ने अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग किया जिसमें दिव्यांग भी शामिल हुए। शकुंतला डोई गैमलिन ने आगे कहा कि भारत ने अलग-अलग दिव्यांग नागरिकों के लिए अलग माहौल की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। भारत विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सार्वभौमिक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, जो विकलांग लोगों को अपने अधिकारों को समान रूप से पूरा करने और उनकी पूर्ण क्षमता का एहसास करने और पूरी तरह से समावेशी देश बनाने में सक्षम हैं जहां सभी समान अधिकारों का आनंद लेते हैं।

मालदीव के एक हजार लोकसेवकों का प्रशिक्षण देने में मदद करेगा भारत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत के प्रमुख लोकसेवा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने मालदीव के एक हजार लोकसेवकों को प्रशिक्षण देने में मदद हेतु मालदीव लोकसेवा आयोग के साथ समझौता किया है। एनसीजीजी और मालदीव सिविल सेवा आयोग के बीच अगले पांच साल के दौरान एक हजार लोकसेवकों के क्षमता निर्माण के लिए ट्रेनिंग देने का समझौता हुआ है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की राजधानी माले की यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय ने दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 08 जून 2019 को मालदीव दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी को विदेशियों को दिए जाने वाले अपने सर्वोच्च सम्मान रूल अहफ निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- हाल ही में केंद्र सरकार ने जितने मंत्रालयों का विलय कर एक नए मंत्रालय जलशक्ति मंत्रालय का सृजन किया है- दो
- वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का 9वाँ संस्करण जिस देश में आयोजित किया जा रहा है- नीदरलैंड
- हाल ही में जिस बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिये गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जारी की है- भारतीय रिजर्व बैंक
- विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून को विश्व भर में मनाया गया। इस वर्ष का थीम रखा गया था- वायु प्रदूषण
- वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रस्ताव पारित करते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 14% से 27% करने का निर्णय लिया है - मध्य प्रदेश
- जिस प्रतिशित वैज्ञानिक को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है - मृत्युंजय मोहपात्रा
- भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के दौरान रेपो रेट में जितने प्रतिशत कटौती का घोषणा किया है-0.25 प्रतिशत
- दूसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है-आठ
- वह देश जिसने हाल ही में पहली बार एक तैरते हुए जहाज से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक रॉकेट लांच किया है- चीन
- अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की वह सांसद जो संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं- प्रमिला जयपाल
- वह राज्य सरकार जिसने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिये एक बाजार-आधारित व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है- गुजरात सरकार
- हाल ही में भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार एवं विश्व बैंक ने तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं-287 मिलियन डॉलर
- जिस देश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा को अपने कार्यकाल के दौरान एक लॉटरी योजना शुरू करने के संबंध में दो साल की सजा सुनाई है- थाईलैंड
- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है- नीति आयोग
- वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में 'आपकी बेटी' योजना के तहत स्कूली छात्राओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ा दिया है- राजस्थान सरकार
- हाल ही में मलयालम अभिनेत्री शीला को जे.सी. डेनियल अवार्ड प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान जिस क्षेत्र में योगदान के लिए दिय गया है- सिनेमा
- भारत के जिस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय फुटबॉलर बन गया हैं- सुनील छेत्री
- फेसबुक ने हाल ही में जिस देश में पहला इंटरैक्टिव गेम शो 'कन्फेटी' लांच किया है- भारत
- भारत मौसम विज्ञान विभाग जिस साल तक देश के 660 जिलों के सभी 6,500 ब्लॉकों के पर मौसम का पूर्वानुमान जारी करने की क्षमता स्थापित करने की परियोजना पर तेजी से काम कर रहा है- साल 2020
- जिस मंत्रालय के तत्त्वावधान में चल रहे जन शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये फीस माफ कर दी गई है- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- इन्हें हाल ही में बीजू जनता दल का संसदीय मंत्री चुना गया है - पिनाकी मिश्रा
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा निधि के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति की दरें बालकों के लिये प्रतिमाह रखी गई है -2500 रुपये
- भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस दूसरे मंत्रालय के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है - कृषि मंत्रालय
- पहली संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा के कार्यकारी बोर्ड के लिये प्लेनरी सत्र हेतु जिस देश को चुना गया है -भारत
- भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें महिलाओं के लिए बसों और मेट्रो ट्रेन में सफर निःशुल्क कर दिया गया है - दिल्ली
- वह शहर जिसे हाल ही में विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित शहर घोषित किया गया है - पुएर्तो विलियम्स
- वह राज्य जिसके स्वास्थ्य विभाग को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया गया -राजस्थान
- वह पाठ्यक्रम जिसे समाप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति के मसौदे में कहा गया है -एम.फिल
- इन्हें हाल ही में पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करने के साथ-साथ कैबिनट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है - अजीत डोभाल
- अमेरिका ने हाल ही में सामान्य प्राथमिकता प्रणाली के तहत जिस देश के उत्पादों को शुल्क में मिलने वाली छूट आगे और जारी न रखने का घोषणा किया है- भारत
- हाल ही में जिस राज्य में निपाह वायरस के पहले संक्रमित व्यक्ति की पहचान की गई है- केरल
- जिस वेबसाइट द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के शीर्ष 15 सबसे गर्म शहरों में भारत के 8 शहर शामिल हैं- एल डोराडो डॉट कॉम
- नीलगिरि के जंगलों में करीब जितने प्रतिशत रॉक पेंटिंग्स (शैल चित्रकला) मानवीय हस्तक्षेप के कारण नष्ट हो रही है-40 प्रतिशत
- किशोर कुमार की पहली पत्नी का नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है- रुमा गुहा
- आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की आशाकर्मियों का वेतन 3,000 रुपये से बढ़ाकर जितने रुपये करने की घोषणा की है-10,000 रुपये
- हाल ही में जिस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को मेक्सिको का विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाने वाले उच्चतम नागरिक सम्मान दिया गया है- प्रतिभा पाटिल
- इटली के सबसे ऊँचे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है जिसमें हाल ही में ज्वालामुखी फट पड़ा है- माउंट एटना
- हाल ही में नौसेना ने जिस देश के समुद्री डकैती को रोकने हेतु 'P-8I लॉन्ग रेंज मेरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट' तैनात किया है- ओमान
- वह देश जिसके विदेश मंत्रालय ने अपने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए वीजा आवेदन हेतु लोगों को अपने विवरण में सोशल मीडिया की विवरण देने का प्रावधान किया है- अमेरिका
- भारत के जिस राज्य में पहली बार एक अस्पताल से दूसरे स्वास्थ्य केंद्र तक ड्रोन से ब्लड सैंपल पहुंचाने का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया - उत्तराखंड
- हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जिस राज्य सरकार की नदी जोड़ो परियोजना पर पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव का हवाला देते हुए रोक लगा दी है - आंध्र प्रदेश
- वह राज्य सरकार जिसने अभिनेता - फिल्मकार - लेखक गिरीश कर्नाड के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक और एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है - कर्नाटक
- हाल ही में जिस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व डीएमके नेता आर.वी. जानकीरमन का निधन हो गया- पुद्दुचेरी
- फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार अमेरिका की सबसे अमीर 80 महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की जिस महिला को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है - जयश्री उलाल
- हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा जिस राज्य के मुख्यमंत्री 'कॉनराड के संगमा' के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है- मेघालय
- भारत में वर्ष 2019 के अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम जिस स्थान पर होगा - रांची
- जिस भारतीय इतिहासकार को अमेरिकन फिलोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया है - रोमिला थापर
- हाल ही में जिस भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है- युवराज सिंह
- विश्व महासागर दिवस विश्वभर में जिस दिन मनाया जाता है - 08 जून
- गृह मंत्रालय ने हाल ही में जिस राज्य के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को आधार बनाकर अवैध रूप से निवास कर रहे विदेशी प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने के लिये विशेष दिशा-निर्देश जारी किये हैं - असम
- हाल ही में जिस देश की सरकार ने नकली दवाओं के उभरते बाजार पर अंकुश लगाने हेतु स्थानीय स्तर पर बेची जाने वाली सभी दवाओं पर बारकोडिंग को अनिवार्य करने की योजना बनाई है - भारत
- प्रधानमंत्री का पदभार दोबारा संभालने के बाद नरेंद्र मोदी दो दिनों की यात्रा पर 8 और 9 जून को पहले मालदीव और उसके बाद जिस देश की यात्रा पर गये थे - श्रीलंका
- भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जो चक्रवाती तूफान लगभग 95 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से गुजरात की ओर बढ़ा - वायु
- हाल ही में सेव द चिल्ड्रेन द्वारा जारी 'एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स' में भारत की रैंकिंग है - 113
- जिसे हाल ही में 17वें लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है - वीरेंद्र कुमार
- हाल ही में ज्ंइसमंन नामक कम्पनी का अधिग्रहण जिस कम्पनी द्वारा किया गया है - सेल्सफोर्स

हिमाचल सामान्य ज्ञान

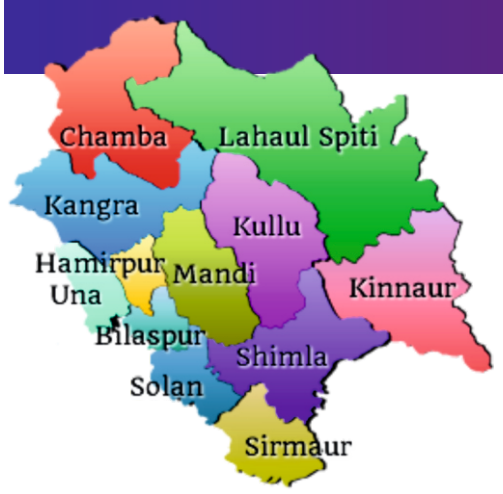

- वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को प्रदेश सरकार द्वारा कितनी पेंशन दी जा रही है-850 रूपये
- हिमाचली बोली मे फिल्म बनाने और 75 प्रतिशत शूटिंग प्रदेश के अंदर होने पर कितनी ग्रांट देने का प्रावधान है- 50 लाख की ग्रांट देने का
- हिमाचल में 70 साल के वृद्धजनों को कितनी पेंशन दी जाती है- 1500
- हाल ही में किन दो रोप वे को मंजूरी मिली है- पलचान से रोहतांग और हिमानी से चामुंडा
- सहारा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है- स्वास्थ्य क्षेत्र से, इसमें सात गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार सहायता प्रदान करती है
- 26 अक्तूबर 2015 को कुल्लू दशहरे के मौके पर कितनी महिलाओं ने नाटी डालकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिर्काड में नाम दर्ज करवाया था-9892
- हिमाचल में कुल कितनी पंचायतें हैं- 3226
- प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कितनी छूट दी जाएगी- 70 प्रतिशत
- हिमाचल के आलू के बीज पर कब तक कृषि मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है-2024
- मनरेगा के तहत हिमाचल इस वर्श कितनी राशि लेगा- 900 करोड़
- पिछले लंबे समय से चर्चा में रहे हाटी समुदाय का संबंध प्रदेश के किस जिले से है- सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र से
- हिमाचल प्रदेश के कौन से हिस्से में हालदा उत्सव मनाया जाता है - लाहौल
- दराती दर्रा कौन से क्षेत्रों को जोड़ता है- चंबा-पांगी
- सन 1966 में हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे - 10
- प्रसिद्ध पाटन घाटी किस जिले से संबंधित है - लाहौल स्पीति
- सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था - बनेड
- झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है - चंबा
- हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? - 3 राज्य सभा व 4 लोक सभा में
- 19वीं सदी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था- अमर सिंह थापा
- किन्नौर जिला कब बनाया गया - 21 अप्रैल 1960 में
- रोरिक आर्ट गैलरी कहां पर स्थित है - नग्गर कुल्लू में
- हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी शैली कौन सी है - बंद छत शैली
- गुरु का लाहौर किस जिले में स्थित है - बिलासपुर
- पीपलू मेला कहां लगता है - ऊना
- हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुस्तकालय कहां पर स्थित है - शिमला
- काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहां मिलता है - लाहौल स्पीति और किन्नौर
- कांगड़ा चाय किस नाम से बिकती है - ग्रीन गोल्ड
- महाशीर, मिरर कोरप, लोबिया रोहित ट्राऊट किस की उत्तम किस्में है ? - मछली की
- हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गी पालन फार्म कहां है ? - पीजेहरा (सोलन)
- आर -आर 21, कल्याण सोना, सोनालिका किस की उत्तम किस्में है - गेहूं की
- हिम 123, गंगा ३, विजय और अंबर किस की उत्तम किस्में है - मक्का की
- लिंकन वुन विला किस की उत्तम किस्म है - मटर की
- कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, गिरिराज, अशोका, पुखराज, जवाहर, किस की उत्तम किस्में हैं - आलू की

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 6000 रुपए की मदद मिलती है। सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को छोड़कर हर गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला को यह मदद मिलती है। इस लेख में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? इसका लाभ पाने के लिए नियम व शर्तें क्या हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या है? और यह भी कि कौन सी स्थितियों में इसका फायदा नहीं मिल सकता।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के निर्देशों के तहत - गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और जच्चा-बच्चा (मां व संतान) को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। 01 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लांच किया था।

इसके माध्यम से हर गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला को 6000 रुपए तक आर्थिक मदद दी जाती है। देश के सभी जिलों समेत हिमाचन में भी इसे लागू किया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का संचालन आंगनवाड़ी केंद्रों या स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से होता है। इस योजना का लाभ सभी आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं को मिल सकता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य?

कमजोर आय वर्ग की महिलाएं आर्थिक तंगी के कारण गर्भावस्था के अंतिम दिनों के दौरान भी रोजगार से संबंधित कामों में लगी रहती हैं। बच्चे के जन्म के बाद भी पर्याप्त आराम के पहले ही काम करना शुरू कर देती हैं, जबकि उनका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता। इससे दोहरा नुकसान होता है।

पहला, महिला खुद के स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान और समय नहीं दे पाती, जिससे वे कमजोरी, रक्ताल्पता, जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो जाती हैं। इसका असर उसकी होने वाली संतान पर भी पड़ता है।

दूसरा, शिशु के जन्म के बाद शुरुआती छह महीनों तक उसे मां के दूध की लगातार जरूरत होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और बच्चे को बाद में भी पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता।

इन दोनों समस्याओं के समाधान के रूप में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजन शुरू की है। इसके तहत कमजोर आयवर्ग की महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि उन्हें मजदूरी में नुकसान के एक हिस्से की भरपाई हो सके। इससे एक तरफ महिला को पर्याप्त विश्राम लेने में सहूलियत होगी और दूसरी तरफ महिला व बच्चे को पोषण के लिए भी मदद होगी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभ किसे?

कुछ निश्चित श्रेणियों को छोड़कर (नीचे उनका जिक्र किया गया है) सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मानी गई हैं।

योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा भी (योजना की शर्तों के तहत होने पर) लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

किसे नहीं मिल सकता लाभ: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जिन श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं माना गया हैं, वे इस प्रकार हैं-

सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में कार्यरत महिलाएं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लाभ नहीं ले सकतीं, क्योंकि, उनकी सेवाशर्तों में वेतन सहित मातृत्व अवकाश जैसे लाभ पहले से ही जुड़े होते हैं।

किसी अन्य कानून से लाभ पा रही **प्राइवेट कर्मचारी** जो महिलाएं किसी प्राइवेट संस्थान में कार्यरत है, लेकिन वहां लागू किसी अन्य कानून के तहत मातृत्व लाभ की सुविधा प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के तहत मदद प्राप्त नहीं कर सकतीं।

पहले कभी सभी किस्तें पा चुकी महिला:

आपने इसके पहले कभी अन्य संतान के जन्म के दौरान, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत पहले सभी किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं, तो भी आप इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारी नहीं हैं।

तीन किस्तों में मिलती है मदद राशि

योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को सरकार से मिलने वाली मदद तीन किस्तों में मिलेगी।

Matru Shakti-Rashtra Shakti

PRADHAN MANTRI MATRU VANDANA YOJANA

- This scheme is being implemented to provide improved health seeking behavior amongst the pregnant women and lactating mothers.
- Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana aims to provide partial compensation for the wage loss in terms of cash incentives in three installments so that the woman can take adequate rest and nutrition before and after delivery of the first living child.

Details of incentives to the beneficiary

Conditionalities and Instalments

Installment	Conditions for claim	Desired Documents for claim	Amount (Rs.)
First Instalment	• Early registration of pregnancy in MCP card (within 150 days)	• Application Form 1 A • MCP Card • Identity Proof (If Aadhaar is not available) • Bank/Post Office Passbook	1,000/-
Second Instalment	• Received at least one ANC (can be claimed after 06 months of pregnancy)	• Application Form 1 B • MCP Card	2,000/-
Third Instalment	• Child Birth is registered • Child has received first cycle of BCG, OPV, DPT and Hepatitis-B or its equivalent/substitute	• Application Form 1 C • MCP Card • Aadhaar Card • Child Birth Certificate	2,000/-

For further information, please contact ASHA/ANM

कब मिलेगी किस्त की राशि

पहली किस्त– आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भधारण का पंजीकरण कराने पर (गर्भ के 150 दिनों के अंदर) 1,000 रुपये

दूसरी किस्त– गर्भधारण के छह माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर (गर्भ के 180 दिनों के अंदर) 2,000 रुपये

तीसरी किस्त– बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने तथा बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हैपेटाइटिस बी आदि टीकों का प्रथम चक्र पूरा होने पर 2,000 रुपये

शेष 1000 रुपए का भुगतान:

योजना के तहत तीन किस्तों में 5000 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन लाभार्थी महिला के किसी संस्था (सरकारी या अनुमोदित अस्पताल) में प्रसव कराने पर जननी सुरक्षा योजना के तहत 1000 रुपए की मदद अतिरिक्त रूप से मिलती है। इस प्रकार प्रत्येक महिला को कुल 6000 रुपए तक मातृत्व लाभ दिया जाता है।

ध्यान रखें कि योजना का फायदा पहली बार मां बनने वाली महिला या पहले जीवित बच्चे के मामले में ही मिलता है।

योजना के लाभ के लिए आवेदन में लाभार्थी महिला व उसके पति को भी इस बात की घोषणा भी करनी होती है कि यदि प्रसव सफल रहा तो यह उनका पहला जीवित बच्चा होगा।

गर्भपात, मृत जन्म, शिशु मृत्यु के मामले में नियम

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का फायदा पहली बार मां बनने वाली महिला या पहले जीवित बच्चे के मामले में ही मिलता है। वास्तव में यह योजना किसी एक महिला को एक बार ही मदद की सभी किस्तें पाने का हक देती है। गर्भपात, मृत जन्म या शिशु मृत्यु की स्थिति में निम्नलिखित तरीकों से लागू होंगे।

गर्भपात के मामले में:

गर्भपात होने पर लाभार्थी महिला की बची हुई किस्तें, आगे कभी गर्भधारण की स्थिति में प्राप्त की जा सकती हैं। बाद के गर्भधारण के दौरान वे किस्तें दोबारा नहीं मिलेंगी, जो पहले वाले गर्भधारण के दौरान उसे मिल चुकी हैं। उदाहरण के लिए किसी महिला को पहले गर्भधारण के दौरान योजना की पहली किस्त मिल चुकी है। इसके बाद अगर उसका गर्भपात होता है तो उसे अगले गर्भधारण व संतान उत्पत्ति के दौरान सिर्फ दूसरी व तीसरी किस्त मिल सकेगी।

मृत शिशु जन्म के मामले में मृत शिशु पैदा होने की स्थिति में भी यही नियम लागू होंगे। यानी कि जो किस्तें पहले मिल चुकी हैं, वे दोबारा नहीं मिलेंगी और जो किस्ते पहले नहीं प्राप्त की गई हैं, उनके लिए अगले गर्भधारण की स्थिति में क्लेम किया जा सकता है।

शिशु मृत्यु के मामले में: शिशु की मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी योजना का लाभ पाने के नियम इसी प्रकार रहेंगे। अगर, लाभार्थी महिला ने योजना के तहत मिलने वाली सभी किस्तें प्राप्त कर ली हैं तो अगले गर्भधारण व

संतान को जन्म देने की स्थिति में वह किसी प्रकार के लाभ का दावा नहीं कर सकती। अगर कोई किस्त बची हुई है तो उसे वह बाद में क्लेम कर सकती है।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लाभ पाने के लिए आपको आसपास मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में संपर्क करना होगा। आंगन बाड़ी कार्यकर्ता, आशा या स्वयं ही आपसे सारी जानकारी लेकर फॉर्म भर देगी और उसे आगे की प्रक्रिया के लिए भिजवा देगी।

कहां करें आवेदन–

आंगनवाड़ी केंद्र: जिन राज्यों में कुपोषण मिटाने की योजना आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभागध्समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है, वहां आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित होगी।

स्वास्थ्य सुविधा केंद्र: जिन राज्यों में कुपोषण मिटाने की योजना आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है, वहां योजना को स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

आवेदन के लिए अर्हता व जरुरी दस्तावेज–

योजना का फार्म भरने के लिए महिला की आयु 19 साल से अधिक होनी चाहिए। मदद की तीनों किस्तों के क्लेम के लिए अलग-अलग फार्म भरे जाएंगे।

हिमाचल मातृवंदना योजना में अव्वल

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से सितंबर 2018 में आयोजित मातृ वंदना सप्ताह समारोह के समापन पर योजना में उल्लेखनीय प्रगति करने पर हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश और राजस्थान को पुरस्कृत किया गया था। इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत केंद्रीय अधिकारियों ने योजना को तेजी से लागू करने की सभी से अपील की।

मातृ वंदना सप्ताह के समापन समारोह में पीएमएमवीवाई (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) में उल्लेखनीय कार्य के लिए नार्थ जोन से हिमाचल प्रदेश, नार्थ-ईस्ट जोन से मिजोरम, पूर्वी जोन से झारखंड, सेंट्रल जोन से मध्य प्रदेश, साउथ जोन से आंध्रप्रदेश और वेस्टर्न जोन से राजस्थान को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हरियाणा के पंचकुला और यमुनानगर, असम के ढिब्रूगढ़, पश्चिम बंगाल के मेदनीपुर और अलीपुरद्वार, मध्य प्रदेश के इंदौर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को योजना में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए सम्मान दिया गया।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना

गांव और शहरों में किसे और कैसे मिल सकता है इस योजना का लाभ?

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अगर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है और आप अपना घर लेने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। पहले जहां इस योजना का लाभ गरीब वर्ग के लिए था वहीं अब इस योजना में लोन की रकम बढ़ाकर शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को भी दायरे में लाया गया है । पहले लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी जिसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है । लेकिन यहां एक बात बार–बार लोगों के दिमाग में आती है, वो ये कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन के लिए क्या जरूरी शर्तें हैं और क्या दस्तावेज जरूरी हैं, कई बार लोग योजना की शर्तों को नहीं समझ पाते हैं और वह इस बेहद लाभकारी योजना से वंचित रह जाते हैं, तो यहां द रीव टाइम्स आपको बताएगा कि इस योजना के लिए सरकार ने कौन–कौन सी श्रेणी बनाई है, किस आय वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, सरकार इस योजना के लिए किसे कितनी सब्सिडी दे रही है और कौन से लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आय वर्ग क्या है?

अगर आप पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आप किस आय वर्ग में आते हैं। अगर आप 3 से 6 लाख रुपए तक के आय वर्ग में आते हैं तो आपको ब्याज पर ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, वहीं 6 से 12 लाख रुपए और 12 से 18 लाख रुपए सालाना आय वर्ग के लोगों का सब्सिडी कम होगी। 1 जनवरी 2017 से इस योजना के लाभ का दायरा बढ़ा दिया गया हैं। मिडिल क्लास के लिए दो श्रेणी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए मध्यम वर्ग (डप्ळ) के लिए दो श्रेणी बनाई गई है । इसमें 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की पहली श्रेणी है जबकि दूसरी श्रेणी 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए की है। अब बताते हैं कि 6 से 18 लाख सालाना आय वर्ग के लोग कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या है इस योजना की शर्तें ।

क्या हैं शर्तें

पीएम आवास योजना का उद्देश्य है कि सभी को पक्का मकान मिले। हां इस योजना की कुछ शर्तें जरूर हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है । सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनके पास पहले से घर है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है । प्रधानमंत्री आवास योजना का नियम है कि लाभ उसे ही मिलेगा जिसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होगा ।

दूसरी शर्त

इस योजना की दूसरी शर्त है कि परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार की किसी योजना के तहत आवास योजना का लाभ ना मिला हो । यदि परिवार में किसी सदस्य को सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ मिला है उसके किसी अन्य सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है ।

तीसरी शर्त

इस योजना के लिए आवेदन के वक्त अविभाजित परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नंबर देना जरूरी है। इसमें पति–पत्नी, और अविवाहित बेटे और बेटी शामिल हैं। शादी के बाद बेटा या बेटी इस योजना के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं।

ज़रुरी निर्देश

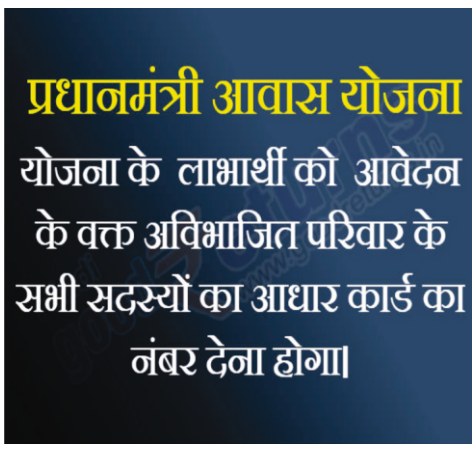

पक्के घर का लाभ उठाने वाले माता–पिता के विवाहित बेटे–बेटियां तो वैसे भी अलग परिवार माने जाते हैं । हालांकि, पति–पत्नी दोनों च्ड।ल का लाभ नहीं ले सकते। यानी, बेटे–बहू या बेटी–दामाद के नाम पर हर हाल में एक ही मकान पर सब्सिडी मिल सकती है । यह उनकी मर्जी होगी कि मकान का मालिकाना हक कोई एक अपने पास रखें या दोनों साथ–साथ ।

अब आपको बताऐंगे कि कितनी ब्याज पर कितनी सब्सिडी देगी सरकार ?

12 लाख प्रति वर्ष आय वर्ग के लोगों के लिए इसी तरह 12 लाख प्रतिवर्ष की आय वाले लोगों को 9 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिसमें ब्याज दर पर 4 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी इसमें मासिक ईएमआई पर 2,158 रुपए की बचत होगी जो कि 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 39 हजार 843 रुपए तक होगी। 12 से 18 लाख आय वर्ग यदि आपकी सालाना आय 12 से 18 लाख रुपए के बीच है तो आपको 12 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दरों में 3 फीसदी की छूट मिलेगी। ये 110 स्क्वायर मीटर में हो रहे घर के निर्माण को लेकर दिए गए लोन पर निर्भर करेगा। 12 लाख रुपए पर 3 फीसदी की सब्सिडी को 20 साल में चुकाना होगा जिसके ब्याज पर मिली कुल छूट 2.30 लाख रुपए होगी। इस तरह से देखा जाए तो सरकार आपके लोन के लिए 2.30 लाख रुपए देगी जो कि आज के वक्त में बड़ी बचत है।

6 लाख सालाना आय वर्ग के लोगों के लिए वहीं 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वालों को 6 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है और ब्याज दर पर सरकार की तरफ से 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। जिससे

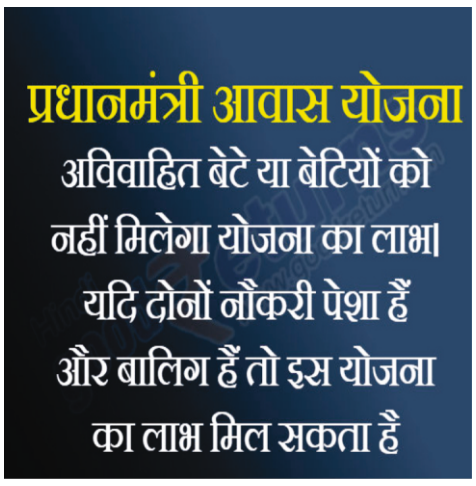

मासिक EMI में 2,219 रुपए की बचत होती है, ये बचत 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 46 हजार 625 रुपए तक होती है ।

समझें ब्याज पर सब्सिडी का पूरा गणित

इसे ऐसे समझें मान लीजिए आपकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए है तो आपको 12 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिस लोन पर सरकार आपको ब्याज दर पर 3 फीसदी की सब्सिडि देगी। इससे प्रतिमाह

आपको 2,200 रुपए की बचत होगी जिसका 20 वर्ष में कुल 2 लाख 44 हजार 468 रुपए लाभ मिलेगा ।

5 साल और बढ़ी सीमा

अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए है तो आपको पीएम आवास योजना पर 20 साल के होम लोन पर 2.4 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हों । पहले लोन चुकाने की सीमा 15 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर अब 20 साल कर दिया गया है । सरकार अब आपके ब्याज पर सब्सिडी देगी जिससे मिलने वाली छूट का लाभ बढ़ जाएगा । इसके लिए सरकार ने रियल स्टेट मार्केट को चुना है ।

घर की मरम्मत कराने के लिए भी मिलेगा लाभ

आप किसी बिल्डर से घर खरीद रहे हैं या कोई पुराना मकान खरीद रहे हैं तो आप च्ड।ल का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग घर खरीदने की बजाय इसे खुद बनवा रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा । जिनके पास अभी पक्का मकान है, वो इसकी मरम्मत करने या इसमें कुछ और कमरे जुड़वाने या किसी दूसरे तरह से इसका विस्तार करने के लिए भी लोन ले सकते हैं । बैंक आपको मौजूदा पक्का मकान में किचन, कमरा आदि बनाने के लिए योजना के तहत लोन देने से यह कहकर इनकार नहीं कर सकता कि आपके पास पहले से ही पक्का मकान है। कार्पेट एरिया हर कैटिगरी के लाभार्थी के अनुसार घर का क्षेत्रफल भी तय है। हालांकि, इसके तहत उसी एरिया को मापा जाता है जो दीवारों से घिरा हो जिसे कार्पेट एरिया कहा जाता है। इसमें दीवार की मोटाई का माप शामिल नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो जिस भाग पर आप दरी बिछा सकते हैं, वही घर का कार्पेट एरिया कहलाएगा। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कार्पेट एरिया 90 वर्ग मीटर यानी 968.752 वर्ग फीट है

जबकि इसी श्रेणी के दूसरे भाग के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए यह 110 वर्ग मीटर यानी 1184.03 वर्ग फीट है।

खत्म हो सकती है कार्पेट एरिया की सीमा

एरिया तय किए जाने से शहरी क्षेत्र में लोग इस योजना के प्रति बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार कार्पेट एरिया की सीमा खत्म कर देगी।

कहां से ले सकते हैं लोन

आप कमर्शल बैंकों, हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, छोटे वित्तीय बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि से लोन लेकर ब्याज पर उचित सब्सिडी पा सकते हैं। आपको किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं देना होगा। हां, आप योजना के तहत जितना लोन लेने के योग्य हैं, उससे ज्यादा लोन ले रहे हैं तो अतिरिक्त रकम पर आपको नॉर्मल प्रोसेसिंग फी देनी पड़ सकती है ।

पीएम आवास योजना के आंकड़े आए सामने

पीएम आवास योजना में अब तक कितने मकान बने और किने लोगों को इसका फायदा मिला, इन सभी बातों की जानकारी अब सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 नवंबर, 2016 को आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक एक करोड़ नये घरों का निर्माण सुनिश्चित किया जाना है । इनमें से 31 मार्च 2018 तक 51 लाख मकान बनाए जाने हैं । इस चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 51 लाख आवास मार्च 2018 तक बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई कदम उठा रहा है। इसके लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि आवासों का निर्माण किया जा सके।

इन राज्यों को हुआ सबसे ज्यादा फायदा

छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। इन राज्यों के लोगों ने निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने आवासों का निर्माण किया है ।

आईए जानते हैं हिमाचल की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत

हिमाचल प्रदेश में इस योजना को अभी और गति पकड़ी होगी। टीम रीव की पड़ताल में इस योजना को धीमी गति से ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें एक कारण तो अनापत्ति प्रमाण पत्रों की कमी तथा दूसरे शहरी क्षेत्रों में ज़मीन का न होना है। क्योंकि जिनके पास शहर में ज़मीन है, वो तो ग़रीब कम ही है और जो किराए दार है उनके पास आय के स्रोत वांछित आंकड़े को भी पार कर देते हैं यानि उनकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होती है। साथ ही कुछ लोग जो बाहरी राज्यों से है और विवाहिताओं को हिमाचल में प्रवेश मिला है, उन्हें राजस्व विभाग की पेचिदगियों से दो–चार होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मुद्दा हमें भी प्राप्त हुआ जहां एक महिला हिमाचल प्रदेश के बाहरी राज्य से हिमाचल में विवाहित हुई। वार्षिक आय 3 लाख से कम ही थी लेकिन राजस्व विभाग में पटवारियों के दस्तावेज़ी औपचारिकताओं में उलझ गई। इसी प्रकार नगर निगम शिमला के अंतर्गत भी इस महत्वकांक्षी योजना को लागु करने में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वर्टिकल 3 के अंतर्गत जो लोग भूमिहीन है तथा मकान की दरकार सबसे अधिक है लकिन शिमला में ऐसे क्षेत्र कम ही है। इसके लिए एक सर्वे 2016 में हुआ जिस पर बाद में कुछ विवाद भी हुआ और पुनः सर्वेक्षण के लिए हामी भरी गई। सर्वे में 3000 के लगभग नाम सामने आए जिनमें से 184 के लगभग ही आवेदन कर पाऐं। बाकी आवेदनों को भी प्रशासन ने जांचने का कार्य चलाया है। अगर वर्टिकल 4 की बात करें तो उसमें लगभग 61 डीपीआर तैयार की गई हैं जिसमें 20 से 22 लोगों का मकान का कार्य अंतिम चरण में हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास या तो अपनी ज़मीन है या पुराना मकान मुरम्मत के लिए है अथवा नये कमरे का निर्माण पुराने मकान के साथ कर रहे हैं। इसमें भी गति को और अधिक तीव्र करने की आवश्यकता रहेगी। नगर निगम शिमला में जुड़ें नए क्षेत्रों में ज़मीन की उपलब्धता कुछ आसानी से हो जाती है इसलिए यहां पर इस योजना को आसानी से लागु किया जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यहां ज़मीन की उपलब्धता रहती है। यह भी देखने में आया है कि आवेदकों में बहुत सी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। किसी न किसी प्रकार से ये लोग इस योजना का लाभ लेकर मकान हासिल करना चाहते है। ऐसे में इस योजना का लाभ पात्र एवं ग़रीब भूमिहीन लोगों को कैसे मिले, यह प्रशासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। भूमिहीन लोगों को रिहायिश किन शर्तों पर मिलेगी और कब तक सभी भूमिहीनों को मकान आबंटित किए जाऐंगें इस पर भी अभी बहुत तीव्रता से कार्य करने की आवश्यकता है। हालांकि सर्वेक्षण का आंकड़ा या आवेदन का 3000 से अधिक हो सकता है परंतु भूमिहीन होने का प्रमाणपत्र केवल 400 के लगभग ही लोग दे पाए हैं। दोनों ही श्रेणियों में इस योजना को लाभान्वितों तक पंहुचाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

केदारनाथ गुफा अब मोदी गुफा के नाम से हो रही सर्च

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ दौरे की गुफा के अंदर साधना करते हुए तस्वीरें वायरल हुई हैं, तभी से बहुत सारे लोग इस गुफा की जानकारी जुटाने में लगे हैं। अंतिम चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने जिस गुफा में रात गुजारकर मेडिटेशन किया वो गुफा रातों रात फेमस हो गई है। इस गुफा का नाम रुद्र मेडिटेशन केव है, जिसे गढ़वाल मंडल विकास निगम ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया था। यह गुफा समुद्र तल से करीब 12000 फीट उंचाई पर छोटी सी जगह पर बनी है। गुफा की सुविधाओं को देखकर लगता है कि यह किसी होटल से कम नहीं है। इस गुफा में बेड, टॉयलेट, 24 घंटे बिजली, टेलीफोन जैसी सुविधाएं हैं। यहां कोई भी जा सकता है। गुफा में वाई फाई की का भी इंतजाम है। गुफा में सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना उपलब्ध कराया जाता है। इस गुफा को पर्यटकों के लिए बनाया गया था, लेकिन बहुत कम ही लोगों ने इसकी बुकिंग की। पीएम मोदी के इस गुफा होकर आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि ये गुफा काफी प्रसिद्ध होगी और इसकी बुकिंग भी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर इस गुफा की चर्चा जोरों पर है। यहां तक कि इंटरनेट पर यूजर्स इस गुफा को ध्यान कुटिया की बजाय मोदी गुफा के नाम से इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक बीएल राणा का कहना है कि इस बात में कोई शक ही नहीं है कि प्रधानमंत्री के यहां आने से यह जगह चर्चा में आ गई है और लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहे हैं। गुफा की बढ़ी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने फिलहाल इस गुफा की बुकिंग पर रोक लगा रखी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून के पहले महीने से एक बार फिर इस गुफा के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी।

आज भी इस किले में यहां मौजूद है पारस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुनिया में आज भी कई ऐसी चमत्कारी चीजें मौजूद हैं, जिनके बारे में लोगों ने किस्सों-कहानियों में सुना है। ऐसा ही एक चमत्कारी पत्थर है पारस पत्थर, जिसके बारे में आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज तक इस पत्थर को कोई नहीं ढूंढ़ पाया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक किले में इसके होने का दावा किया जाता है। यही वजह है कि हर साल किले में लोग खुदाई करने पहुंच जाते हैं। पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये वो पत्थर है जिसे छूते ही लोहा भी सोना बन जाता है। माना जाता है कि भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में यह पत्थर मौजूद है। कहा जाता है कि इस किले के राजा के पास पारस पत्थर मौजूद था। इस पत्थर के लिए कई बार युद्ध हुए, लेकिन जब इस किले के राजा को लगा कि वह युद्ध हार जाएंगे तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में मौजूद तालाब के अंदर फेंक दिया। राजा ने ये किसी को नहीं बताया कि पारस पत्थर को कहां छुपाया है। बाद में युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और देखते ही देखते ये किला भी वीरान हो गया।

कान में मकड़ी ने बुन दिया जाला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सोशल मीडिया में पिछले दिनों कुछ फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शरीर में आंख, कान, नाक, गला सबसे ज्यादा नाजुक अंग माने जाते हैं। इन अंगों के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो यह जान पर भी बन आती है।

दरअसल, चीन से एक ऐसे शख्स की खबर सामने आई है जिसके कानों में बेहद खतरनाक संक्रमण फैल गया था। कान के इलाज का मेडिकल परीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसका एक बेहद डरावना वीडियो सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक मकड़ी ने एक शख्स के कान में घुसकर जाला बुन लिया। 60 साल के इस शख्स ने डॉक्टर के पास जाकर शिकायत की कि उसे सोने के समय असहज महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके कान में कोई ड्रम बजा रहा हो। चीनी व्यक्ति ने डॉक्टर को बताया कि उसके कानों में पिछले कुछ समय से खुजली हो रही है। जब डॉक्टर ने उसके कान का परीक्षण किया तो हैरान करने वाली बात सामने आई। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि उसके कान के अंदर एक जिंदा मकड़ी ने अपना डेरा जमा लिया था। इतना ही नहीं उसने वहां पर अपना जाला भी बुनना शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि उस व्यक्ति को अपने कानों में इचिंग की शिकायत आ रही थी। कान, नाक और गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने शख्स के कान की जांच का एक वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर ने वीडियो पोस्ट करके लिखा कि एक बूढ़ा आदमी हमारे पास शिकायत लेकर आया की उसके कान में कोई कीड़ा है। हमने जांच की तो पता चला की उसके कान में मकड़ी थी और उसने जाल भी बुन रखा था। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक दाने के बराबर की मकड़ी शख्स के कान में दो इंच अंदर तक थी। यहां तक की वीडियो में दिख रहा है कि उसने अपने आपको बचाने के लिए कई जाले भी बुन रखे थे। डॉक्टरों ने ये भी बताया है कि मकड़ी के शख्स के कान में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। डॉक्टरों ने पहले तो शख्स के कान में कोई शिकायत नहीं पाई। लेकिन जब उन्होंने कान में माइक्रोस्कोप लगाकर अंदर देखा तो हैरान रह गए।

ये है अनोखा जुगाड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय करते नजर आते हैं। एक ऐसा ही उपाय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर तो मजबूर कर ही दिया है, साथ ही इस अनोखे उपाय के बारे में जानकर लोग अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं। दरअसल, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक शख्स ने भयंकर गर्मी से बचने के लिए अपनी कार को ऐसे कलर से रंग दिया है, जिसे छूने से भी लोग कतरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सेजल शाह नाम के शख्स ने गाड़ी को गोबर से रंगा है। हालांकि यह गाड़ी रमनिकलाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिस पर महाराष्ट्र का नंबर है। फेसबुक यूजर रुपेश गौरंग दास ने उस कार की तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है, 'गाय के गोबर का सही इस्तेमाल' इससे पहले मैंने आज तक नहीं देखा। 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से बचने के लिए सेजल शाह ने अपनी कार को ही गाय के गोबर से रंग दिया है। वहीं, लोग अब उस फेसबुक पोस्ट पर सवाल पूछ रहे हैं कि कार के अंदर बैठे लोग गर्मी से तो शायद बच जाते होंगे, लेकिन गोबर की दुर्गंध से कैसे बचते हैं। हालांकि भारत में ऐसी मान्यता है कि गाय का गोबर घर को ठंडा रखता है, इसलिए गांवों में कई लोग अभी भी दीवारों पर गोबर ही लगाते हैं।

एम्स में भारत का पहला मल्टी-स्क्लेरोसिस क्लिनिक खोला जायेगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत में लोगों को स्कलेरोसिस बीमारी से बचाने, रोग को फैलने से रोकने तथा इस महामारी के संबंध में अध्ययन करने, के लिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लीनिक खोलने की अत्यधिक आवश्यकता है।

एम्स-दिल्ली द्वारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बेहतर निदान और उपचार के लिये देश का पहला मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लिनिक खोला जायेगा। एम्स द्वारा यह क्लिनिक जून के दूसरे सप्ताह में खोला जायेगा।

भारत में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, बड़े पैमाने पर इस महामारी के संबंध में अध्ययन करने, समर्पित मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लीनिक खोलने, इष्टतम पुनर्वास आदि जैसी अन्य सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है।

मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है?

मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा रोग है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही माइलिन (वसायुक्त पदार्थ जो तंत्रिका तंतुओं के चारों और स्थित होता है तथा आवरण के रूप में काम करता है), तंत्रिका तंतुओं तथा शरीर में माइलिन का निर्माण करने वाली विशेष कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाती है।

- इसके लक्षण सामान्य होते हैं, इसलिये लोग अक्सर इस बीमारी को जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। इस बीमारी के निदान में लंबा समय लग जाता है।
- यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और दृष्टि से संबंधित नसों को प्रभावित करती है।
- इसके अन्य लक्षणों में शामिल हैं - मांसपेशियों की कमजोरी और अकड़न, मूत्राशय की समस्याएँ: मरीज को मूत्राशय में समस्या महसूस होती है, बार-बार या अचानक पेशाब करने की आवश्यकता होती है, मूत्राशय पर नियंत्रण का खत्म हो जाना इस बीमारी का प्रारंभिक संकेत है। रीढ़ की हड्डी में क्षतिग्रस्त तंत्रिका तंतु, धुंधली या दोहरी दृष्टि की समस्या, भावनात्मक परिवर्तन और अवसाद, संज्ञानात्मक (निर्णय लेने में समस्या) नुकसान।

मल्टी-स्क्लेरोसिस क्लिनिक की आवश्यकता

- यह बीमारी पश्चिम के देशों में अधिक प्रचलित रही है, लेकिन हाल के दिनों में भारत में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं।
- 20-40 वर्ष आयु वर्ग के वयस्क, विशेष रूप से महिलाएँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस की चपेट में आती हैं।
- भारत में लोगों को इस बीमारी से बचाने, रोग को फैलने से रोकने तथा इस महामारी के संबंध में अध्ययन करने, समर्पित मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लीनिक खोलने की अत्यधिक आवश्यकता है।

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा।

द रीव टाइम्स

दूरभाष : 9418404334

Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिलों, गांव, स्वास्थ्य, कानून, समसामयिक विषयों पर संपादकीय एवं अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान दर्पण, सरकारी जनपयोगी योजनाओं का संपूर्ण दस्तावेज़.....द रीव टाइम्स

उत्कृष्ट गुणवत्ता, संपूर्ण रंगीन पृष्ठ, शानदार विषयवस्तु के साथ प्रदेश का पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स अब आपको मिलेगा घर-द्वार पर ही। समाचार पत्र को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट http://sub.missionriev.in पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मिशन रीव के कार्यकर्ता/अधिकारी से संपर्क कर भी आप कैशलैस भुगतान कर इसके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। अब आपके लिए आकर्षक ऑफर.....

अब वार्षिक सदस्य बनें केवल 500/रूपये, छः माह के लिए 250/रूपये में और घर बैठे पांऐ द रीव टाइम्स.....क्योंकि आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़